www.hindmatamirror.com • वर्ष: 12 • अंक: 257 • ठाणे, शुक्रवार 19 जून, 2026 • पेज: 8 • मूल्य: 2 रुपए hindmatamirror1@gmail.com

RNI. NO. MAHHIN/2011/43060

दैनिक

हिंदमाता मिरर

पैनी नजर, पुख्ता खबर

पेज 8

'लेडी सिंघम' बनीं करीना कपूर

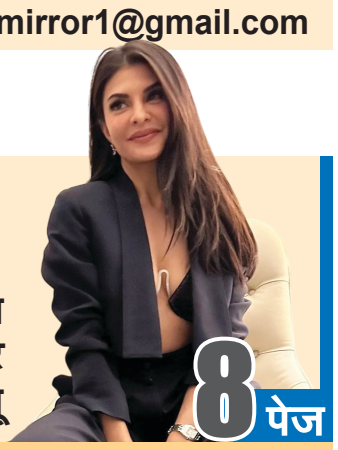

जैकलीन करेंगी हॉरर जॉनर में डेब्यू

8 पेज

सुप्रभात

वे गुलाम हैं जो पतित और दुर्बलों के लिए नहीं बोल सकते। वे गुलाम हैं जो अति अल्पमत में होने पर भी सत्य का पक्ष नहीं ले सकते। - **लॉवेल**

मौसम का मिजाज

सूर्यास्त (19 जून) 7:18 बजे, सूर्योदय (20 जून) 6:02 बजे, **तापमानः 33 डिग्री से. (धूप खिली रहेगी।)**

शॉर्ट स्टोरी

'आतंकी गतिविधियों का अड्डा बना टेलीग्राम'

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत सरकार ने सिक्योर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को हफ्ते भर के लिए बैन कर दिया है। टेलीग्राम ने कोर्ट में चैलेंज भी किया है। टेलीग्राम को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि टेलीग्राम आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक प्लेटफॉर्म बन गया है। मामले की सुनवाई से पहले सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि इस केस में विस्तृत जवाब कोर्ट रजिस्ट्री में दाखिल कर दिया गया है। जैसे ही यह रिकॉर्ड पर आएगा, सुनवाई शुरू होगी। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि टेलीग्राम को बुलाया गया था और उनकी बात सुनी गई।

एआई से बनी तस्वीरों पर भड़कीं प्रीति जिंटा

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के गलत इस्तेमाल के मुद्दे को लेकर अब अभिनेत्री प्रीति जिंटा बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने मेटा और गूगल जैसी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी अनुमति के बिना एआई की मदद से उनकी नकली तस्वीरें और कंटेंट बनाए गए और उन्हें इंटरनेट पर फैलाया गया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। प्रीति जिंटा ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी राइट्स के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अभय आहूजा की बेंच ने मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है।

63 लाख के पुलिस रोबोट की गई नौकरी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

एआई और रोबोटिक्स को पुलिसिंग का फ्यूचर माना जा रहा है। दुनिया के कई शहरों में पुलिस की मदद के लिए रोबोट तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ओहायो राज्य के डबलिन शहर में चलाया गया एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। करीब एक साल तक ड्यूटी करने के बाद शहर के रोबोट पुलिसकर्मी 'डबबॉट' को रिटायर कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस रोबोट ने अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान न तो किसी अपराधी को पकड़वाया, न किसी की गिरफ्तारी में मदद की और न ही एक भी चालान कटवाया। इसके बावजूद प्रोजेक्ट पर करीब 63 लाख रुपए खर्च करने पड़े।

75 उम्मीदवारों से 1.73 करोड़ की ठगी

हिंदमाता नेटवर्क @ ठाणे

नवी मुंबई में आकर्षक नौकरियों का वादा करके 75 उम्मीदवारों से 1.73 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में एक शिपिंग कंपनी के मालिकों और कर्मचारियों सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। खारघर में शिपिंग कंपनी के कार्यालय में काम करने वाले आरोपियों ने पीड़ितों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का लालच दिया। खारघर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने नौकरी की चाह रखने वाले 75 उम्मीदवारों से पिछले दो महीने में 1,73,81,400 रुपए एकत्र किए, लेकिन उन्हें वादे के मुताबिक रोजगार नहीं दिलाया।

● महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे का बढ़ता कद

● महाराष्ट्र में कांग्रेस के बाद शिवसेना बनेगी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी

● शिवसेना यूबीटी के 6 सासंदों के बाद अब कई विधायक भी शिंदे के संपर्क में

'तेरह' सांसदों के साथ किसका 'बारह' बजाएंगे शिंदे?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अक्सर अपनी सभाओं में कहते रहते हैं कि भले ही उनके पुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के मामले में वे किसी से कम नहीं हैं। ठाकरे की शिवसेना को तोड़ देने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए एकनाथ शिंदे अक्सर गर्वोक्ति करते हैं- कैसा ऑपरेशन किया... कैसे तांगा पलट दिया... कैसे बल्लेबाजी की...। अब एक बार फिर शिंदे ने 'ऑपरेशन टाइगर' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। वैसे मेडिकल क्षेत्र में ऑपरेशन करने का मतलब 'बीमारी को जड़ से मिटाना' होता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में दिल्ली दरबार की 'अदृश्य महाशक्ति' के बूते आए दिन जो 'ऑपरेशन' किए जा रहे हैं; वे एक तरह से 'स्वस्थ लोकतंत्र' को पहले से कहीं अधिक बीमार बना रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत के तोड़-फोड़ के खेल ने एक तरह से पुरोगामी महाराष्ट्र को 'हंसी का पात्र' बना दिया है। खैर, पांच किलो राशन और पंद्रह सौ रुपल्ली की खैरात पर बिकनेवाले 'मतदाता राजा' और करोड़ों रुपए लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर आयातित उम्मीदवारों को टिकट पकड़ानेवाले 'पार्टी-विधाता' देश में इन दिनों चल रहे राजनीति तोड़-फोड़ के खुले खेल फरुर्खाबादी पर सवाल उठाने का कितना नैतिक अधिकार रखते हैं?... यह शोध का विषय है। लेकिन फिलहाल वस्तुस्थिति यह है कि 'ऑपरेशन टाइगर' हो चुका है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के छह विधायक किसी न किसी कारण से पाला बदल चुके हैं। पिछले एक साल से एकनाथ शिंदे 'ऑपरेशन टाइगर' को अंजाम देने के लिए मुंबई-दिल्ली एक किए हुए हैं। अब उन्हें सफलता मिली है। आगामी एक-दो दिन में ठाकरे के पाले से शिंदे के पाले में ये सांसद खुलकर आ जाएंगे और इसके साथ ही शिंदे के पास तेरह सांसदों की संख्या हो जाएगी। शिंदे खेमे के एमएलसी कृपाल तुमाने की माने तो ठाकरे खेमे के सोलह विधायक भी शिंदे के संपर्क में हैं। अब तेरह सांसदों के साथ किसका बारह बजाने की तैयारी शिंदे करेंगे। महाराष्ट्र की सडांध मारती सियासत की थोड़ी-बहुत जानकारी रखनेवाले जानकारों का कहना है कि शिंदे हमेशा से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ठाकरे के सांसद, विधायक, नगरसेवक तोड़कर दिल्ली दरबार की 'अदृश्य महाशक्ति' को गदगद कर चुके शिंदे अब निश्चित ही महाराष्ट्र की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पाना चाहेंगे। ऐसा होता है, तो महाराष्ट्र में अभी और राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। 'ऑपरेशन टाइगर' के बाद संभवतः 'ऑपरेशन कुर्सी' का नया चरण शुरू हो सकता है।

लगातार बढ़ता जा रहा है शिंदे का राजनीतिक कद

महाराष्ट्र की सियासत में फिर भूचाल मचाने वाले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कद राज्य की राजनीति में लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद नया गुट बनाकर उनके साथ हो जाते हैं तो सूबे में शिंदे सेना कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। सत्तारूढ़ महायुति में सांसदों के मामले में शिंदे गुट बड़ा भाई होगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने मुंबई व ठाणे सहित राज्य में अपना जनाधार मजबूत किया है। लोकसभा, विधानसभा और निकाय संस्थाओं के चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। शिंदे गुट के पास सांसदों और विधायकों का मजबूत समर्थन है।

कांग्रेस के बाद शिंदे गुट सबसे बड़ा दल

सत्ता पक्ष महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन सरकार चलाने के लिए बीजेपी को एकनाथ शिंदे के समर्थन की जरूरत रही है। ठाकरे सेना के 6 सांसदों का साथ मिलने के बाद शिंदे गुट का संसदीय संख्या बल 7 से बढ़कर 13 हो जाएगा। कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर शिंदे सेना होगी। महायुति में सबसे ज्यादा शिंदे सेना के सांसद होंगे। भाजपा के 9 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक सांसद है। विपक्षी दल महाविकास आघाडी के संख्या बल पर गौर करें तो कांग्रेस 14 सांसदों के साथ पहले नंबर है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के 8 और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के 9 सांसदों में केवल 3 सांसद रह जाएंगे।

उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं कई विधायक

एक भरोसेमंद सूत्र ने दावा किया कि अगर शिंदे शिवसेना यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में लाने में सफल हो जाते हैं तो अगले दो महीनों के भीतर बड़ी संख्या में विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ठाकरे खेमे ने इस बीच 22 जून को विधायकों और एमएलसी की भी अहम बैठक रखी गई है।

एनडीए की ताकत बढ़ने वाली है

लोकसभा में 293 सांसदों के समर्थन से केंद्र में एनडीए सरकार बनी थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों की बगावत के कारण यह आंकड़ा अब 300 के पार पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे खेमे के छह सांसदों के पाला बदलने से भी एनडीए को फायदा हो सकता है, क्योंकि खबरों के अनुसार वे लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं।

बगावत करना जनता से धोखा

शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुस्से में संजय राऊत द्वारा कहे गए अपशब्दों पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना होगा। पार्टी का नाम और सिंबल छीने जाने की लड़ाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि जनता ने ये वोट उद्धव ठाकरे के चेहरे पर दिए थे, इसलिए बगावत करना जनता से धोखा है। पार्टी ने स्पीकर को पत्र लिखकर व्हिप जारी कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका उल्लंघन करने वाले सांसदों को तुरंत अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

रिक्शा की औकात नहीं, विमान से घूम रहे

शिवसेना (यूबीटी) से राज्यसभा सांसद संजय राऊत खुलकर बागी नेताओं पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले उन्होंने दावा किया एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए 2 सांसदों को नांदेड़ से ले जाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इन नेताओं की रिक्शा में बैठने की औकात नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी सांसदों को अपशब्द भी कहे। संजय राऊत ने लिखा था, नांदेड हवाई अड्डे पर एक चार्टर्ड विमान उतरता है, ऑपरेशन के नाम पर 2 सांसदों को उठाकर निकल जाता है। इनकी रिक्शा में घूमने की औकात नहीं थी, निजी विमान से घूमने जितनी कीमत ठाकरे नाम की वजह से बढ़ी। उन्होंने कहा कि हर एक चीज का हिसाब किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि ये 2 सांसद कौन थे।

राजनीतिक पंडितों को खल रहा है फडणवीस का मौन!

महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार को एक बड़ी उठापटक देखने को मिली। पहले से लगाई जा रही अटकलों के अनुरूप शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। इस बगावत के बाद इन सांसदों के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। शिंदे की शिवसेना ने भी ऐलान किया है कि उनके नेतृत्व में विश्वास दर्शाने वाले सभी लोगों का पार्टी में स्वागत है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मौन राजनीतिक पंडितों को खल रहा है। हालांकि भाजपा नेता और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले से भाजपा का कोई संबंध नहीं है।

शिवसेना यूबीटी की व्हिप वाली मीटिंग में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद

6 बागी सांसद लापता

● अनिल देसाई बोले- नोटिस भेजकर मांगेंगे जवाब

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की संसदीय दल की बैठक में कुल नौ लोकसभा सांसदों में से महज तीन ही पहुंचे। दिल्ली स्थित संसद भवन में बुलाई गई इस बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे ने ही हिस्सा लिया, जबकि शेष छह सांसद अनुपस्थित रहे। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राऊत भी मौजूद रहे। बैठक के बाद संजय राऊत ने कहा कि बिना सूचना के बैठक से गायब रहने वाले सांसदों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है। उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेगी।

व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसदों को भेजेंगे नोटिस

बागी सांसदों को कहना है कि उन्हें अब पार्टी नेतृत्व पर भरोसा नहीं रह गया है। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने 6 सांसदों की गैरहाजिरी पर कहा कि व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा।

बागी नेताओं के चेहरे पर गोबर पोतने की धमकी

इस बीच सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर के शिव सेना (यूबीटी) से बगावत करने की चर्चाओं की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र में उनके धाराशिव निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेताया है कि पार्टी छोड़ने वालों के चेहरे पर गोबर पोता जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को धोखा देने वालों को धाराशिव में खुलेआम बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा।

संजय राऊत शुरू करेंगे ऑपरेशन 'तुडवा'

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राऊत ने आक्रामक जवाबी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। राऊत ने अब 'ऑपरेशन तुडवा' (आम भाषा में पिटाई अभियान) शुरू करने का बड़ा दावा किया है। राऊत का साफ कहना है कि गद्दारी करने वाले बागी सांसदों और उन्हें शह देने वाली शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी के खिलाफ अब असली खेल शुरू होने जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मची इस भारी खलबली के बीच, उद्धव खेमे ने साफ कर दिया है कि वे इस राजनीतिक दगाबाजी को इतनी आसानी से नहीं पचने देंगे।

बागी सांसदों को 10-10 करोड़ रुपए और दिए गए

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राऊत ने गुरुवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के बागी सांसदों को 10-10 करोड़ रुपए और दिए गए हैं और उन्हें राजस्थान में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। उन्होंने कहा, शिवसेना (उबाठा) के बागी सांसदों को अतिरिक्त 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे पहले उन्हें 15-15 करोड़ रुपए दिए गए थे।

संसद, अदालत और सड़क पर होगी लड़ाई

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजय राऊत का यह 'ऑपरेशन तुडवा' केवल एक बयानबाजी नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैडर्स को एकजुट रखने का एक आखिरी और बड़ा दांव है।

बागियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी!

सूत्रों के अनुसार 'ऑपरेशन तुडवा' के तहत उद्धव ठाकरे और खुद संजय राऊत उन सभी 6 बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्रों, परभणी, धाराशिव, हिंगोली, वाशिम, शिरडी और उत्तर पूर्वी मुंबई का सघन दौरा करेंगे। पार्टी इन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर जन-आंदोलन खड़ा करेगी ताकि मतदाताओं को यह बताया जा सके कि उनके वोट को किस तरह चंद रुपयों और लालच के लिए दिल्ली के दरबार में बेच दिया गया। राऊत का दावा है कि इस ऑपरेशन के जरिए न केवल बागियों के गढ़ को तोड़ा जाएगा, बल्कि शिंदे गुट के भीतर भी असंतुष्ट नेताओं में बड़ी सेंधमारी की जाएगी।

ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों को मिली वाई प्लस सुरक्षा

महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों की सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस को इन सांसदों को वाई प्लस श्रेणी के बराबर स्थानीय सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा गया है।

रोहित पवार का सरकार पर तीखा तंज

● नीट पेपर लीक पर री-एग्जाम, तो सांसद लीक होने पर री-इलेक्शन क्यों नहीं?

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र में जारी ऑपरेशन टाइगर और सांसदों की संभावित बगावत के बीच, एनसीपी शरद पवार गुट के युवा नेता रोहित पवार ने एक ऐसी दलील पेश की है जिसने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रोहित पवार ने देश में चल रहे नीट पेपर लीक विवाद की तुलना महाराष्ट्र की आयाराम-गयाराम की राजनीति से करते हुए नैतिकता और न्याय का सवाल उठाया है। रोहित पवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर नीट जैसी परीक्षा में पेपर लीक होने पर पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है और री-एग्जाम आयोजित की जाती है, तो फिर विधायकों और सांसदों की फूट के बाद री-इलेक्शन क्यों नहीं कराए जाते? उन्होंने सवाल किया कि क्या यही न्याय है कि छात्रों के लिए नियम अलग और सत्ता के गलियारों में बैठने वाले नेताओं के लिए अलग हों?

ईमानदार छात्र और ठगा गया मतदाता

रोहित पवार ने पेपर लीक और राजनीतिक दलबदल के परिणामों के बीच एक गहरी समानता दिखाई है। उनके अनुसार, जिस प्रकार पेपर लीक होने से केवल धोखेबाजों की चांदी होती है और प्रामाणिक छात्रों पर अन्याय होता है, ठीक उसी तरह विधायकों और सांसदों की फूट से केवल उन पाला बदलने वाले नेताओं के घरों में संपत्ति और समृद्धि आती है। दूसरी ओर, जिन आम मतदाताओं ने उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर चुनकर भेजा था, उन पर राजनीतिक अस्थिरता और विश्वासघात की आपदा आन पड़ती है।

महादेव बेटिंग नेटवर्क से जुड़े केस में ईडी का बड़ा एक्शन

विकास गर्ग परिवार की 930 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

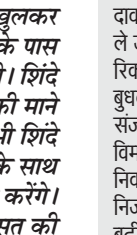

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप नेटवर्क से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी की जांच के दायरे में ईबिक्स इंक के चेयरमैन विकास गर्ग हैं। आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट से जुड़े अपराध की कमाई को विदेशी निवेश और अन्य माध्यमों से वैध दिखाकर अपनी कंपनियों में लगाया और काले धन को सफेद बनाने की कोशिश की। ईडी ने अब विकास गर्ग परिवार के स्वामित्व वाली एराया लाइफस्पेस लिमिटेड के करीब 893 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर अटैच कर दिए हैं। यह कंपनी ईबिक्स इंक से जुड़ी हुई है। इसके अलावा दिल्ली स्थित आवास और कार्यालय, गोवा, नैनीताल समेत अन्य स्थानों पर मौजूद संपत्तियां भी अटैच की गई हैं। कुल मिलाकर जब्त की गई संपत्तियों का मूल्य 930 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है।

ढोंगी बाबा सात सहयोगियों सहित गिरफ्तार

15 साल तक महिला का शोषण, पेशाब पीने को किया मजबूर

हिंदमाता नेटवर्क @ पुणे

पुणे से अंधविश्वास की आड़ में रूह कंपा देने वाले शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक कथित बाबा ने खुद को अलौकिक शक्तियों का स्वामी बताकर एक महिला को डेढ़ दशक तक बंधक जैसी स्थिति में रखा। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके गिरोह को दबोच लिया है। पुणे में एक ढोंगी बाबा और उसके सात सहयोगियों को एक महिला का 15 साल तक यौन उत्पीड़न, शारीरिक प्रताड़ना और वित्तीय शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कथित अपराध एक शिकायत मिलने के बाद सामने में आया, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और ढोंगी बाबा राधामोहन मिश्रा सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पीड़िता को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया

आरोपियों ने दैवीय शक्तियां होने का झांसा देकर इस कृत्य को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए 7 सहयोगियों में 6 महिलाएं शामिल हैं। पीड़िता को लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया। शिकायत के मुताबिक, इस दौरान पीड़िता को बिजली के झटके दिए गए, बेरहमी से पीटा गया और यहां तक कि उसे आरोपी का मूत्र पीने के लिए भी विवश किया गया।

छापेमारी में जब्त हुए कई सामान

शिकायत के आधार पर पुणे पुलिस ने खराड़ी क्षेत्र में स्थित ढोंगी बाबा मिश्रा के आश्रम पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान पुलिस ने 8 लैपटॉप, 19 हार्ड डिस्क, 10 डीवीडी, 9 मोबाइल फोन, 20 कैसेट और 23 पेन ड्राइव जब्त कीं। इसके अलावा लगभग 6.5 लाख रुपए की नकदी और 15 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। परिसर से बड़ी मात्रा में दवाइयां भी मिली हैं, जिनमें से कुछ की मियाद पूरी हो चुकी थी। इनका उद्देश्य पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

हिंदमाता एंकरः क्या कुपढ़ छात्रों की फौज खड़ा करना चाहती है सरकार? ओडिशा के सरकारी स्कूलों में सत्र 2026 की क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की किताबों में बड़ी चूक दिखी

न्यूटन बने 'महान पायलट', ओडिशा की स्कूली किताबों में 1678 गलतियों से मचा बवाल

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

जिस किताब से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में अगर वैज्ञानिक को पायलट और ऐतिहासिक स्थलों की गलत पहचान दी जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ओडिशा के सरकारी स्कूलों की नई पाठ्यपुस्तकों में सैकड़ों गलतियां मिलने के बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ओडिशा में सरकारी स्कूलों के 2026-27 शैक्षणिक की नई किताबों पर विवाद हुआ है। राज्य में क्लास 1 से लेकर 8 तक की नई पुस्तकों में 1,678 गलतियां सामने आने के बाद विभाग ने कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षकों की शिकायत के बाद सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

न्यूटन को वैज्ञानिक नहीं महान पायलट बताया गया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ओडिशा करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत तैयार की गई इन किताबों की स्कूल स्तर पर समीक्षा के दौरान कई कमियां आना सामने आई है। शिक्षकों ने बताया की पुस्तकों में स्पेलिंग मिस्टेक तथ्य और संदर्भ से जुड़ी बड़ी संख्या में गलतियां मौजूद हैं। इसमें हद तो तब हो गई जब न्यूटन को वैज्ञानिक नहीं महान पायलट बताया गया।

सबसे ज्यादा विवाद किस गलती पर हुआ?

सबसे ज्यादा विवाद न्यूटन को वैज्ञानिक की जगह महान पायलट बताया गया। इसके अलावा कई तस्वीरें और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान भी गलत तरीके से प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर को ओडिशा विधानसभा बताया गया है, जबकि हंपी मंदिर परिसर की तस्वीर को कोणार्क का सूर्य मंदिर बताया गया है।

विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में भी मिली बड़ी चूक

विज्ञान और भूगोल से जुड़े कई उदाहरण में गलतियां मिला जहां कुछ जगह गेहूं को धान, तापमान को दबाव, और फूड वेब को फूड साइकिल बताया गया। वहीं नियमगिरि पहाड़ियों की लोकेशन और बरहमपुर की प्रशासनिक पहचान भी गलत बताई गई है। जिससे शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने दिए जांच के आदेश

किताबों में लगातार गलतियां निकालने के बाद ओडिशा सरकार ने उसे उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं। सरकार यह अब यह पता लगाएगी की किताबों की तैयारी और प्रशासन प्रक्रिया में इतनी बड़ी संख्या में गलती कैसे रह गई। इसके साथी विपक्ष ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही बताया है।

नवीन पटनायक ने क्या कहा?

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने कहा कि सैकड़ों गलतियों का पता चलने से सरकार का लापरवाह और पूरी तरह से असंवेदनशील रवैया उजागर हुआ है। एक्स पर एक पोस्ट में पटनायक ने आरोप लगाया कि छात्रों को पहले ही पाठ्यपुस्तकें मिलने में देरी का सामना करना पड़ा था और जो किताबें आखिरकार उन्हें मिलीं तो उनमें ढेर सारी गलतियां थीं। ओडिशा में स्कूली किताबों में आई इस गड़बड़ी ने एक बात तो साफ कर दी है कि सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर नहीं है। ऐसे में पढ़े-लिखे कुपढ़ों की फौज तैयार होने का खतरा है।

महाराष्ट्र में सूचना मांगने के लिए उद्देश्य बताना अनिवार्य?

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

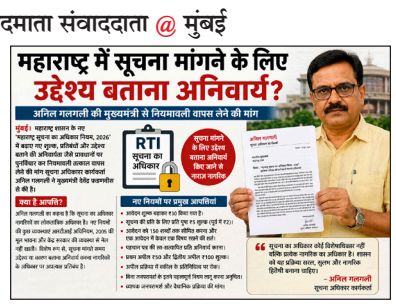

महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक साप्रवि/१२०२०/४/२०२५-साप्रवि-कार्या-६ के माध्यम से घोषित 'महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026' में बढ़ाए गए शुल्क, सूचना प्राप्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों तथा नागरिकों के सूचना अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर पुनर्विचार कर नियमावली तत्काल वापस लेने की मांग सूचना अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। महाराष्ट्र में सूचना मांगने के लिए उद्देश्य बताना अनिवार्य किए जाने से नागरिकों में नाराजगी है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अनिल गलगली ने कहा है कि सूचना का अधिकार नागरिकों का लोकतांत्रिक और प्रभावी अधिकार है, जो शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार नियंत्रण का महत्वपूर्ण माध्यम है। किंतु नए नियमों की कुछ व्यवस्थाएं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल भावना एवं केंद्र सरकार की वर्तमान व्यवस्था से मेल नहीं खाती प्रतीत होती हैं। विशेष रूप से, नए नियमों के तहत नागरिकों को सूचना मांगते समय सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य या कारण बताना अनिवार्य किए जाने पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। अनिल गलगली ने कहा कि सूचना का अधिकार व्यवस्था की मूल भावना के अनुसार नागरिकों को सूचना मांगने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए तथा ऐसी शर्त सूचना प्राप्ति के अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध का कारण बन सकती है।

पत्र में निम्न प्रमुख आपत्तियां दर्ज की गई हैं

- आवेदन शुल्क बढ़ाकर 30 किया गया है, जो आम नागरिकों के लिए आर्थिक बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- सूचना की प्रति के लिए प्रति पृष्ठ 5 शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि पूर्व व्यवस्था और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार 2 प्रति पृष्ठ शुल्क लागू है।
- आवेदन को 150 शब्दों तक सीमित करना तथा एक आवेदन में केवल एक विषय रखने की शर्त अनावश्यक प्रतिबंध मानी गई है।
- आवेदन के साथ नागरिकता सिद्ध करने हेतु पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करने की अनिवार्यता प्रक्रिया को जटिल बना सकती है।
- प्रथम अपील हेतु 50 तथा द्वितीय अपील हेतु 100 शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की गई है।
- अपील प्रक्रिया में विधि व्यवसायी (एडवोकेट) के प्रतिनिधित्व पर रोक को अनुचित बताया गया है।
- इतने महत्वपूर्ण नियम लागू करने से पहले सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए थीं।
- नियमों को लागू करने से पूर्व वैधानिक प्रक्रिया और व्यापक जनपरामर्श सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

■ अनिल गलगली ने मांग की है कि इन सभी बिंदुओं पर पुनर्विचार होने तक 'महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026' के अमल पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा नागरिकों, सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर अधिक जनहितकारी एवं पारदर्शी संशोधित नियमावली जारी की जाए। 'सूचना का अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। शासन को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, सुलभ और नागरिक हितैषी बनाना चाहिए, ऐसा अनिल गलगली ने कहा।

एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने 20 आरोपियों को दबोचा

● यूपी में छापा, 22 .79 करोड़ का मादक पदार्थ नेटवर्क बेनकाब

हिंदमाता संवाददाता @ वसई

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा कक्ष-4 ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संचालित एक गुप्त एमडी ड्रग्स (मेफेड्रॉन) निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 2.07 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। अब तक इस अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट से कुल 22.79 करोड़ रुपए का माल बरामद किया जा चुका है तथा 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

कई राज्यों तक पहुंचा नेटवर्क

जांच के दौरान पुलिस ने मुंबई के आग्रीपाड़ा, मालवणी, मनोरी तथा तेलंगाना के जहीराबाद क्षेत्र में छापेमारी कर 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहां से एमडी ड्रग्स, रासायनिक पदार्थ और प्रयोगशाला उपकरण समेत 20 .72 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया।

हरदोई में मिला मुख्य अड्डा

पुलिस को जांच के दौरान उत्तर प्रदेश में इस नेटवर्क के मुख्य ठिकाने की जानकारी मिली। 16 जून को हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र से तसलीम आरिफ छुट्टन उर्फ रज्जाक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारा।

करोड़ों का सामान जब्त

छापेमारी में 1.026 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, 300 लीटर रसायन, हीटिंग ड्रायर, सेपरेशन फ्लास्क, रिकवरी फ्लास्क, बुकनर फनल सहित ड्रग्स निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरण जब्त किए गए। इनकी कुल कीमत 2 .07 करोड़ रुपए बताई गई है।

जांच जारी

पुलिस के अनुसार, इस अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क की जड़ें और किन-किन राज्यों तक फैली हैं, इसकी जांच जारी है। यह कार्रवाई अपराध शाखा कक्ष-4 के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद बडाख, सहायक निरीक्षक प्रशांत गांगुर्डे, दत्तात्रय सरक तथा उनकी टीम और साइबर सेल के सहयोग से की गई।

मीरा रोड से शुरू हुई जांच

पुलिस ने 4 अप्रैल 2026 को मीरा रोड पूर्व स्थित बैंक रोड की एक इमारत में रहने वाली महिला फिरदोस अरबाज कुरैशी के घर पर छापा मारकर 2.66 करोड़ रुपए मूल्य का 1.324 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया था। जांच में यह माल उसके पति अरबाज वकील कुरैशी का होने का खुलासा हुआ। इसके बाद नयानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई।

स्कूल की छत पर आग बड़ा हादसा टला

समय रहते आग पर काबू

हिंदमाता संवाददाता @ भायंदर

मीरा रोड के हाटकेश क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल की इमारत में गुरुवार दोपहर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हालांकि अग्निशमन दल और स्कूल सुरक्षा कर्मचारियों की तत्परता के कारण आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

टेरेस पर लगी आग

जानकारी के अनुसार, हाटकेश इलाके के सेंट डोमिनिक सैवियो हाईस्कूल की छत पर गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे आग लगी। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि टेरेस पर रखे कबाड़ सामग्री के पास शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़की।

समय पर खाली था स्कूल

गनीमत रही कि स्कूल की छुट्टी दोपहर करीब एक बजे हो चुकी थी और सभी विद्यार्थी घर जा चुके थे। इससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता

अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले ही स्कूल के सुरक्षा रक्षकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को पूरी तरह बुझाकर परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया।

जांच जारी

घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, हालांकि आग से कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी प्रकाश बोराडे के अनुसार, आग लगने के सटीक कारण और नुकसान के आकलन के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।

नालासोपारा पूर्व के अलकापुरी क्षेत्र में सड़क किनारे बड़े पैमाने पर कचरे के ढेर जमा होने से स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कचरे से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास का वातावरण प्रदूषित हो गया है। वहीं, आवारा गायें और अन्य पशु इस कचरे में भोजन तलाशते नजर आ रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल सफाई अभियान चलाने और सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। **(फोटो- सचिन हलदे)**

पार्षद का कुणबी जाति प्रमाणपत्र निकला फर्जी

हिंदमाता नेटवर्क @ दौंड

दौंड नगर परिषद के पार्षद रोहित पाटिल का कुणबी जाति प्रमाणपत्र जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने जांच के बाद फर्जी पाया गया। रोहित पाटिल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से चुनाव जीता था, लेकिन उनके इस प्रमाणपत्र को फर्जी दावों के आधार पर चुनौती दी गई थी। समिति के इस कड़े फैसले के बाद अब पाटिल का पार्षद पद पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है, जिससे स्थानीय राजनीति में भारी हड़कंप मच गया है। इस संदर्भ में रतन जाधव, एड। सुशांत वाघमारे, सचिन कुलथे, मृणाल ढोले पाटिल, अनिकेत भागवत आदि शिकायतकर्ता के वकील मंगेश ससाणे ने दी जानकारी के अनुसार, रोहित पाटिल ने कुणबी प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए ऐसे लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।

भाजपा कार्यालय का उद्घाटन

वन मंत्री गणेश नाईक ने विकास का दिया भरोसा

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका मुख्यालय में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के गटनेता कार्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र के वन मंत्री एवं पालघर जिले के पालकमंत्री गणेश नाईक के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, महापौर नारायण रतन चौधरी, विधायक महेश चौघुले, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माधवीताई नाईक तथा भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविकांत सावंत सहित अनेक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

शक्ति प्रदर्शन की झलक

मनपा मुख्य प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल स्थित कक्ष क्रमांक 201 में स्थापित कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के निमंत्रक भाजपा गटनेता संतोष मंजय्या शेट्टी थे। राजनीतिक हलकों में इसे आगामी मनपा चुनावों से पहले भाजपा के संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

विकास पर जोर

समारोह को संबोधित करते हुए गणेश नाईक ने कहा कि भिवंडी की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही शहर में जरूरत के अनुसार सड़क, नाला, पुलिस चौकी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ऑटिज्म जागरूकता शिविर 28 जून को

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

हैदराबाद स्थित रिस्प्लाइस ऑटिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फाउंडेशन द्वारा 28 जून को ठाणे में ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों और परिवारों के लिए निःशुल्क गट हेल्थ असेसमेंट एवं माइक्रोबायोम टेस्टिंग शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर दादोजी कोंदेव स्टेडियम परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर थोडुपुनुरी ने बताया कि संस्थान ऑटिज्म की रोकथाम और उपचार से जुड़े शोध कार्यों पर केंद्रित है। उनका दावा है कि ऑटिज्म की शुरूआत गर्भावस्था के दौरान हो सकती है और समय रहते उचित सावधानियां अपनाकर जोखिम को कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से संस्था ने ऑटिज्म प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू किया है। डॉ. थोडुपुनुरी के अनुसार, फाउंडेशन गट-ब्रेन एक्सिस पर आधारित शोध कर रहा है तथा फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन (एफएमटी) थेरेपी के संभावित लाभों का अध्ययन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटिज्म के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता और रोकथाम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फाउंडेशन ने 'ऑटिज्म मुक्त भारत अभियान' और 'सेव माइक्रोबायोम एंड सेव हेल्थ' जैसे राष्ट्रीय अभियान भी शुरू किए हैं। संस्था ने अभिभावकों से शिविर का लाभ उठाने और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की है।

सड़क निर्माण पर घमासान

संजय केलकर ने वीजेटीआई ऑडिट और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को लेकर ठाणे महानगर पालिका भाजपा विधायक संजय केलकर के निशाने पर है। केलकर ने शहर के बालकुम, ढोकाली, दोस्ती जैसे अन्य इलाकों में 55 करोड़ के प्रस्तावित कंक्रीट सड़क के काम की पोल खोल दी है। उन्होंने सड़क पर जेसीबी चलवाकर सड़कों की खराब गुणवत्ता को उजागर किया। साथ ही नाला सफाई में की जा रही हाथ सफाई पर भी नाराजगी जतायी है। उन्होंने सडकों का वीजेटीआई से ऑडिट कराने एवं नाला सफाई के ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की मांग मनपा प्रशासन से की है।

600 करोड़ रुपए बगैर ब्याज का कर्ज

ठाणे मनपा ने केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपए बगैर ब्याज का कर्ज लिया है। इसी निधि में से 55 करोड़ रुपए की लागत से बालकूम, ढोकली, दोस्ती सहित इलाकों में चार कंक्रीट सड़कों के काम किए जा रहे हैं।

फेरीवालों पर बड़ी कार्रवाई

डोंबिवली में तीन टेम्पो सामान जब्त

हिंदमाता संवाददाता @ डोंबिवली

डोंबिवली पूर्व के जी और एफ प्रभाग में अवैध फेरीवालों के खिलाफ प्रशासन पिछले तीन महीनों से लगातार अभियान चला रहा है। एफ प्रभाग में अधिकांश फेरीवाले हट चुके हैं, लेकिन जी प्रभाग के उर्सेकरवाड़ी और डॉ. रॉथ रोड क्षेत्र में फेरीवाले अब भी डटे हुए हैं। बढ़ते अतिक्रमण और नागरिकों की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने हाल ही में विशेष अभियान चलाकर तीन टेम्पो सामान जब्त किया।

नागरिकों की बढ़ती परेशानी

रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में फेरीवालों की वजह से पैदल चलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को रोजाना भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर नगरसेवकों ने भी नाराजगी जताई है और आयुक्त से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

महासभा में उठा मुद्दा

हाल ही में हुई महासभा में नगरसेविका रंजना पेणकर और उपमहापौर राहुल दामले ने फेरीवालों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र को फेरीवालों से मुक्त कराने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे। उनका आरोप है कि कार्रवाई के बावजूद फेरीवाले दोबारा कब्जा जमा लेते हैं।

रणनीति से की कार्रवाई

एफ प्रभाग के सहायक आयुक्त प्रसाद ठाकुर ने विशेष रणनीति अपनाते हुए पहले क्षेत्र का गुप्त निरीक्षण किया। उन्होंने सामान्य यात्री की तरह रेलवे टिकट लेकर स्काईवॉक और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की तथा यह जानकारी जुटाई कि फेरीवाले अपना सामान कहां छिपाते हैं और किन दुकानों में रखते हैं।

तीन टेम्पो माल जब्त

इसके बाद जी और एफ प्रभाग की संयुक्त टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर दुकानों और गोदामों में छिपाकर रखा गया सामान बाहर निकाला। कार्रवाई के दौरान तीन टेम्पो भरकर माल जब्त किया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से फेरीवालों में हड़कंप मच गया और कई लोग मौके से भाग निकले।

स्थायी समाधान की मांग

नगरसेवकों का कहना है कि फेरीवालों की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन एकजुट होकर कार्रवाई करें। वहीं, आयुक्त अभिनव गोयल ने कहा है कि डोंबिवली को अवैध फेरीवालों से मुक्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सुरक्षा एआरसी के प्रमोटर सुधीर वालिया की जमानत खारिज

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

सत्र न्यायालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रमोटर सुधीर वालिया को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला वर्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज लगभग 1000 करोड़ रुपए के कथित वित्तीय घोटाले और संपत्ति हड़पने के आरोपों से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल डी. सालुंखे ने 18 जून 2026 को सुनाए गए आदेश में कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं और जांच के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता लखमिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2016 से 2018 के बीच यस बैंक के अधिकारियों ने नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी कंपनी के लगभग 1000 करोड़ रुपए मूल्य की गिरवी रखी गई संपत्तियों से जुड़े ऋण खाते को सुरक्षा एआरसी को हस्तांतरित कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यस बैंक के अधिकारियों और सुरक्षा एआरसी से जुड़े लोगों ने आपसी मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश रची।

जांच एजेंसी ने कहा कि पूरे आर्थिक अपराध की सच्चाई सामने लाने और सभी संबंधित दस्तावेजों तथा लेन-देन की जांच के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और केस डायरी के अध्ययन से प्रथम दृष्टया गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप सामने आते हैं। न्यायालय ने माना कि मामले की गंभीरता, कथित वित्तीय अनियमितताओं की राशि और आरोपी की भूमिका को देखते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। इसी आधार पर अदालत ने सुधीर वालिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया।

शादी के 48 दिन बाद विशाखा ने की आत्महत्या

डॉक्टर पति घर के अंदर सीसीटीवी से रखता था नजर

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

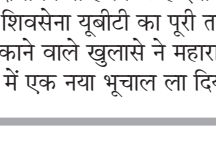

ठाणे जिले के अंबरनाथ क्षेत्र से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के महज 48 दिन बाद एक 26 वर्षीय नवविवाहिता विशाखा तिलकर ने ससुराल वालों के जानलेवा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। विशाखा की शादी बीते 30 अप्रैल 2026 को डॉक्टर नितिन तिलकर से हुई थी। मृतका के परिवार का आरोप है कि विवाह से पहले सब कुछ पूरी तरह सामान्य था, लेकिन विदाई के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों का असली और लालची चेहरा सामने आ गया। विशाखा पर लगातार मायके से मोटी रकम, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान लाने का दबाव बनाया जा रहा था।

सीसीटीवी कैमरे में कैद थी विशाखा की निजी जिंदगी

विशाखा के परिजनों ने उसकी वैवाहिक जिंदगी को लेकर जो खुलासे किए हैं, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। परिजनों के मुताबिक, उसके पति डॉक्टर नितिन तिलकर ने घर के अंदर के कमरों और बाहर के रास्तों पर कई हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। इन कैमरों के जरिए विशाखा की हर छोटी-बड़ी गतिविधि, उठने-बैठने और यहां तक कि उसकी सांसों पर भी सख्त नजर रखी जाती थी। इस खौफनाक निगरानी के कारण उसकी निजी जिंदगी (प्राइवेसी) पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। विशाखा को घर के बाहर किसी भी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति से बात करने की सख्त मनाही थी। लगातार हो रहे इस क्रूर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से पूरी तरह टूट चुकी विशाखा ने आखिरकार मौत को गले लगा लिया। इस स्तब्ध कर देने वाली घटना के बाद अंबरनाथ के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुख्य आरोपी पति डॉ. नितिन तिलकर, उसकी मां छाया तिलकर और भाई निनाद तिलकर पर कार्रवाई करते हुए पति नितिन तिलकर को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

हिंदमाता एंकरः बागी सांसदों के प्रस्ताव में चौंकाने वाला खुलासा

कांग्रेस में हो सकता है शिवसेना यूबीटी का विलय!

हिंदमाता संवाददाता @ मीरा-भायंदर

महाराष्ट्र के सियासी महा-संग्राम और 'ऑपरेशन टाइगर' के बीच एक ऐसा सनसनीखेज और अभूतपूर्व खुलासा हुआ है, जिसने उद्धव ठाकरे खेमे की राजनीतिक जमीन हिलाकर रख दी है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 बागी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष प्रस्तुत किए गए आधिकारिक प्रस्ताव की प्रति से यह साफ हो गया है कि आखिरकार इन सांसदों ने अचानक 'मातोश्री' का साथ क्यों छोड़ा। एक न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, बागी सांसदों ने अपने प्रस्ताव में दावा किया है कि उन्हें इस बात की प्रबल आशंका थी कि आने वाले समय में शिवसेना यूबीटी का पूरी तरह से कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा। इस चौंकाने वाले खुलासे ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया है।

कांग्रेस में विलय के लिए नहीं हुआ था पार्टी का जन्म

बागी सांसदों द्वारा पारित और हस्ताक्षरित इस गुप्त प्रस्ताव में वैचारिक मतभेदों का खुलकर जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में साफ तौर पर लिखा गया है कि वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना कांग्रेस की नीतियों के विरोध में और प्रखर हिंदुत्व के लिए की थी, न कि भविष्य में कभी कांग्रेस के साथ विलीन होने के लिए। सांसदों ने आरोप लगाया कि मौजूदा शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से अपनी मूल विचारधारा से समझौता कर रहा था, उससे दल के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा था। इसी टूटते भरोसे और वैचारिक भटकाव के कारण सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से अपना विश्वास पूरी तरह खत्म होने की बात कही है।

संजय राऊत के 'टीएमसी' वाले बयान से भड़के सांसद

प्रस्ताव के मुताबिक, इस ऐतिहासिक बगावत की पटकथा के पीछे शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता संजय राऊत का एक हालिया बयान भी बेहद जिम्मेदार रहा है। सांसदों ने प्रस्ताव में सीधे तौर पर राऊत के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा है कि कुछ समय पहले संजय राऊत ने सार्वजनिक मंच से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में विलय करने की अजीब सलाह दी थी। राऊत के इस बयान के बाद से ही इन 6 सांसदों के भीतर यह डर घर कर गया था कि जो नेता दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस में मिलने की सलाह दे रहे हैं, वे भविष्य में अपनी खुद की पार्टी शिवसेना यूबीटी का विलय भी कांग्रेस में करा सकते हैं।

सीधे एकनाथ शिंदे की 'शिवसेना' में होगा आधिकारिक विलय

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण और कानूनी रूप से मजबूत पहलू यह है कि इन बागी सांसदों ने खुद को लोकसभा में किसी नए या स्वतंत्र समूह के रूप में मान्यता देने की मांग नहीं की है। उनके द्वारा पारित कानूनी प्रस्ताव के अनुसार, वे सभी 6 सांसद सीधे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली 'शिवसेना' में शामिल हो रहे हैं। मीडिया में अब तक चल रही 'अलग गुट' की अटकलों के विपरीत, बागी धड़े का स्पष्ट दावा है कि दो-तिहाई बहुमत होने के कारण उनका यह कदम तकनीकी और कानूनी रूप से मूल शिवसेना में सीधा विलय माना जाएगा, जिससे उनकी संसद सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी।

'सीडबॉल' टीम का 10 लाख पौधे लगाने का संकल्प

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली मराठी फिल्म 'सीडबॉल' की टीम ने 10 लाख वृक्षारोपण का संकल्प लेकर एक प्रेरणादायी पहल की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फिल्म की अंतिम शूटिंग वृक्षारोपण अभियान के साथ संपन्न की गई, जिसमें कलाकारों और तकनीकी टीम ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। साज एंटरटेनमेंट और थर्ड आई क्रिएशन के बैनर तले निर्मित यह फिल्म पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण जैसे गंभीर विषयों पर आधारित है। फिल्म के माध्यम से नई पीढ़ी को प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जाएगा। 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ' का संदेश कहानी के हर पहलू में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में कमलेश सावंत, अवनी चव्हाण, चित्रा देशमुख, कल्याणी नाईक, रमेश चांदणे, बबन जोशी, रुद्र ढोरे, श्रुति चव्हाण और विकास थोरात प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं बाल कलाकार रुद्र पुणवत, अथर्व सुर्वे, विघ्नेश शिंदे और सलोनी बालगुडे ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी और निर्देशन अखिल देसाई ने किया है। निर्माण की जिम्मेदारी अखिल देसाई और ज्योति बडेकर ने संभाली है, जबकि अनिल देवळेकर सह-निमार्ता हैं। अंतिम शूटिंग के दौरान पूरी टीम ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और 10 लाख पौधे लगाने के जनजागरण अभियान में सक्रिय भागीदारी का संकल्प व्यक्त किया। पर्यावरण जागरूकता पर आधारित यह फिल्म जल्द ही दर्शकों के सामने आएगी।

मुंबई के चर्चगेट स्थित ऐतिहासिक क्रॉस मैदान में मानसून के आगमन से पहले रखरखाव और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। बारिश के मौसम में क्रिकेट मैच और अभ्यास अस्थायी रूप से बंद रहने के कारण मैदान की मिट्टी को समतल करने, घास की देखभाल करने और पिचों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। आगामी क्रिकेट सत्र के लिए मैदान को बेहतर स्थिति में तैयार किया जा रहा है। इसके चलते फिलहाल बल्ले से टकराती गेंद की आवाज और खिलाड़ियों का उत्साहपूर्ण शोर कुछ समय के लिए थम जाएगा।
फोटो : सचिन हल्दे

रविवार को भी वर्किंग-डे की तरह चलेंगी ट्रेनें

मुंबई लोकल का नीट छात्रों को बड़ा तोहफा, नहीं होगा मेगा ब्लॉक

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें इस रविवार एक खास मिशन पर होंगी। अक्सर रविवार के दिन जहां मुंबई वासी छुट्टी के मूड में होते हैं और ट्रेनों की संख्या कम रहती है, वहीं इस बार नजारा कुछ अलग होगा। मध्य रेलवे ने घोषणा की है कि आगामी 21 जून, 2026 यानी रविवार को होने वाली नीट-यूजी 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेनें अपने पूरे वर्किंग डे शेड्यूल के अनुसार चलेंगी।

नहीं होगा कोई मेगा ब्लॉक

रविवार का दिन रेलवे के रखरखाव और मेगा ब्लॉक के लिए जाना जाता है, जिससे अक्सर रूट डाइवर्ट होते हैं या ट्रेनें देरी से चलती हैं। लेकिन 21 जून को छात्रों की राह में कोई रुकावट न आए, इसके लिए मध्य रेलवे ने किसी भी रूट पर कोई मेगा ब्लॉक न रखने की पुष्टि की है।

1,478 नहीं, अब दौड़ेंगी 1,820 ट्रेनें

अमूमन रविवार के दिन मध्य रेलवे पर ट्रेनों की संख्या घटाकर 1,478 कर दी जाती है, जिससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा होती है। लेकिन परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, रेलवे प्रशासन ने इस रविवार को भी सप्ताह के आम दिनों की तरह सभी 1,820 लोकल सेवाएं चलाने का फैसला किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए छात्रों को भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।

एनटीए की छात्रों से अपील

एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी छात्रों का मनोबल बढ़ाने में जुटी है। पिछले महीने पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द हुई परीक्षा के बाद, अब यह पुन: परीक्षा 21 जून को आयोजित की जा रही है। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए छात्रों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी और वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह या शोर पर ध्यान न दें। एजेंसी ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों का वादा करते हुए कहा है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों के हितों की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही, परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए छात्रों को मानस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन- 14416, से मदद लेने की सलाह भी दी गई है। कुल मिलाकर, प्रशासन और रेलवे ने मिलकर छात्रों के लिए मैदान तैयार कर दिया है, ताकि वे बिना किसी मानसिक या यातायात के तनाव के अपनी परीक्षा दे सकें।

रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, लाखों का माल जब्त

हिंदमाता नेटवर्क @ वर्धा

वर्धा जिले के आवीं व समुद्रपुर थाना क्षेत्र में पुलिस व राजस्व प्रशासन ने रेत माफियाओं के विरुध्द बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, तीन वाहन व रेत सहित कुल 63 लाख 77 हजार रुपयों का माल जब्त किया गया, प्रकरण में 8 आरोपियों के विरुध्द पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आर्वी पुलिस ने खुबगांव में टीप्पर से रेत की ढुलाई हो रही थी। भनक लगते हो उपविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में नायच तहसीलदार साईकिरन अबुलवार, पुलिस पाटिल रोशन सवाले, राजस्व सेवक अर्जुन दांडेकर ने पुलिस की मदद से नाकाबंदी की। 12 पहिया टीप्पर क्रमांक एमएच 27 डीएस 8181 को रोका गया। टीपर में 10 ब्रास रेत भरी हुई थी। बिना अनुमति व रॉयल्टी के रेत की ढुलाई व चोरी हो रही थी। टीम ने टीप्पर व रेत लगभग 25 लाख 70 हजार रुपए का माल जब्त कर लिया। प्रकरण में आर्वी पुलिस ने अमरावती के कैम्प रोड निवासी चालक भूषण चव्हाण व टीप्पर मालिक अमरावती निवासी अभिषेक मोरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी कार्रवाई समुद्रपुर पुलिस ने आरंभा टोल नाके पर की, जहां से ट्रक क्रमांक एमएच 32 एजे 7137 व दस ब्रास रेत ऐसा कुल 31 लाख का माल जब्त कर लिया गया, प्रकरण में पेठ अहमदपुर निवासी जुनेद मोहम्मद खान (28), वर्धा के गॉडप्लाट निवासी अमजद रफीक शेख व जाकीर हुसेन कालोनी निवासी जुबेर लियाकत खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

6 बार टूट चुकी है शिवसेना

● उद्धव के कार्यकाल में ही 4 बार बगावत, निकलीं कई नई पार्टियां

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र की सियासत में मराठी अस्मिता के नाम पर 1966 में बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया। शिवसेना अपने सियासी इतिहास में छह बार टूट चुकी है और एक बार फिर उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 लोकसभा सांसद अलग होकर एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लिया है। इस तरह बालासाहेब ठाकरे के सियासी विरासत संभाल रहे उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में चार बार पार्टी में बगावत हो चुकी है। शिवेसना (यूबीटी) चार साल में दूसरी बार टूटी है। शिवसेना लगभग हर दशक में टूटती और बिखरती रही है। शिवसेना से निकलकर छगन भुजबल से लेकर नारायण राणे और राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना ही छीन ली। एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने किसी तरह से शिवसेना (यूबीटी) बनाया, लेकिन चार साल के बाद अब उनके 9 में से 6 लोकसभा सांसद अलग हो गए। ये उद्धव ठाकरे की सियासत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवसेना में कब-कब बगावत का सामना करना पड़ा है?

शिवसेना गठन के कुछ साल बाद बगावत

बालासाहेब ठाकरे ने साठ के दशक में शिवसेना की बनियाद रखी। 19 जून 1966 को बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना के राजनीतिक दल के रूप में गठन किया। शिवसेना के बने कुछ ही दिन हुए थे कि शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे और मुंबई के एक नेता बंदू शिंगरे के बीच तनाव हो गया। साल 1974 में मुंबई में लोकसभा उपचुनाव होना था। इस चुनाव में बाल ठाकरे ने कांग्रेस के उम्मीदवार रामराव आदिक को समर्थन देने का फैसला किया। बंधु शिंगरे शिवसेना के कद्दावर नेता थे और मुंबई के परेल-लालबाग मिल मजदूर इलाके में उनकी पकड़ थी। वे बाल ठाकरे के कांग्रेस को समर्थन देने के इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। इसी चलते ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। शिवसेना से बाहर निकलने के बाद बंधु शिंगरे ने शिवसेना के समानांतर एक नया संगठन खड़ा किया। उन्होंने अपनी इस नई पार्टी का नाम 'प्रति शिवसेना'रखा। हालांकि, उनकी पार्टी कोई खास असर नहीं छोड़ सकी।

शिवसेना में दूसरी बगावत छगन भुजबल ने की

शिवसेना के गठन के बाद से यह पार्टी अपने आक्रामक हिंदुत्व और क्षेत्रीय अस्मिता के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और बड़े नेताओं का बाहर निकलना एक ऐतिहासिक सच्चाई रही है। 1991 में छगन भुजबल का बगावत करना शिवसेना के लिए पहला बड़ा झटका था, जिसने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को चुनौती दी।शिवसेना के 52 विधायक जीतकर आए थे। छगन भुजबल चाहते थे कि पार्टी उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए। बालासाहेब ठाकरे ने भुजबल की जगह पर मनोहर जोशी को बना दिया, जिसके चलते भुजबल नाराज हो गए। भुजबल ने 17 शिवसेना विधायकों के साथ बगावत कर दी। पहली बार किसी बहुत बड़े कद के नेता ने पार्टी में विरोध के सुर उठाए थे। तब महज कई विधायकों ने कथित तौर पर विधानसभा स्पीकर को समर्थन पत्र सौंपा था और दूसरे गुट को शिवसेना बी माना गया था। भुजबल ने 17 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर वे शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए।

नारायण राणे ने बगावत कर बनाई अलग पार्टी

नारायण राणे शिवसेना के दिग्गज नेता हुआ करते थे। बाला साहेब ठाकरे ने राणे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तक बनाया था। बालासाहेब ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया तो नारायण राणे को ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि पार्टी में उनकी और उनके समर्थकों की अनदेखी की जा रही है। नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद चरम पर पहुंच गए थे। राणे का आरोप था कि उद्धव ठाकरे के पास राजनीतिक करिश्मा नहीं है और वे जमीनी कार्यकर्ताओं से कट चुके हैं। ऐसे में नारायण राणे ने 2004 में उद्धव ठाकरे के साथ मतभेदों के चलते शिवसेना को अलविदा कहा। शिवसेना से अलग होकर नई स्वाभिमान पार्टी का गठन किया, इसके बाद कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में शामिल हो गए।

उद्धव के चलते राज ठाकरे ने बनाई पार्टी

बालासाहेब ठाकरे की उंगली पकड़कर राजनीति में आए राज ठाकरे खुद को सियासी वारिस मान रहे थे। बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया तो राज ठाकरे नाराज हो गए। ठाकरे परिवार में आंतरिक मतभेद और उद्धव ठाकरे के बढ़ते कद से असंतुष्ट होकर राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस का गठन किया। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर 9 मार्च 2006 को अपनी नई राजनीतिक पार्टी 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' बनाया। इस तरह शिवसेना दो हिस्सों में बट गई। ठाकरे परिवार और शिवसेना के इतिहास का सबसे बड़ा पारिवारिक और संगठनात्मक विभाजन माना जाता है। शुरूआती सफलताओं के बावजूद, पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ को बरकरार नहीं रख सकी और वर्तमान में शून्य पर है।

उद्धव ठाकरे से छीन ली शिंदे ने शिवसेना

उद्धव ठाकरे के सिपहसलार माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में उनके हाथ से सत्ता और पार्टी दोनों ही छीन ली। 2022 में सिर्फ नेता नहीं बल्कि शिवसेना ही दो हिस्सों में टूट गई। शिवेसना के 40 विधायक उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लिया, जिसके चलते शिवसेना दो हिस्सों में बट गई। मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन उद्धव न ही पार्टी बचा सके और न ही चुनाव सिंबल। दोनों पर शिंदे का कब्जा हो गया। शिंदे के नेतृत्व में बहुमत विधायक और सांसद अलग हो गए। 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया विद्रोह ने उद्धव ठाकरे की राजनीति को गहरा झटका दिया। यह केवल कुछ नेताओं का पार्टी से बाहर जाना नहीं था, बल्कि पार्टी के मूल जनाधार और विधानमंडल के एक बड़े हिस्से का पाला बदल लेना था। शिंदे गुट ने इखढ के साथ मिलकर सरकार बनाई और आधिकारिक शिवसेना का नाम और तीर-कमान चुनाव चिन्ह हासिल कर लिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे को नई पार्टी बनाई बनानी पार्टी चुनाव सिंबल भी नया बनाना पड़ा।

उद्धव ठाकरे को फिर लगा सियासी झटका

एकनाथ शिंदे के द्वारा शिवसेना छीने जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवेसना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नाम से पार्टी बनाई, जिसे शिवसेना (यूबीटी) भी कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह टाइगर के बजाय मशाल मिला। शिंदे खुद को कानूनी रूप से असली शिवसेना बताते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने किसी तरह से फिर पार्टी को खड़ा किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी से 9 लोकसभा सांसद जीतकर आए, जिसने उन्हें एक नई सियासी संजीवनी दी। हालांकि, उसके कुछ दिनों के बाद ही विधानसभा चुनाव हुए तो शिंदे के पलड़ा भारी रहा। यहीं से सारा गेम फिर बदलने लगा। 2026 आते-आते उद्धव ठाकरे के लोकसभा सांसद बागी राह पर चल पड़े। बुधवार को 9 में से 6 लोकसभा सांसद ने स्पीकर को पत्र लिखकर अलग गुट बनाने की मांग की। माना जा रहा है कि उद्धव का साथ छोड़ने वाले सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला सकते हैं। इस तरह उद्धव की पार्टी दो धड़ों में बंट गई।

यूबीटी सांसदों के संभावित दल-बदल पर अंजली दमानिया का सवाल

क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है?

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के कुछ सांसदों के संभावित दल-बदल की चचाओं के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके पीछे कहीं देवेंद्र फडणवीस बनाम अमित शाह के बीच कोई राजनीतिक एंगल तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सांसदों के अचानक चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचने और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की खबरें कई सवाल खड़े करती हैं। सियासी जानकारों का दावा है कि महाराष्ट्र सहित देश की झ राजनीति में लगातार बढ़ते देवेंद्र झ फडणवीस के कद पर लगाम लगाने के लिए शाह ने शिंदे का कदम बढ़ाने खेल खेला है। इसी पृष्ठभूमि में दमानिया ने पूछा कि चार्टर्ड फ्लाइट का खर्च किसने उठाया। यदि सांसद केवल शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं तो उन्हें पहले अमित शाह से मिलने की जरूरत क्या है। उनके अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की देरी पर नाराजगी दमानिया ने सुको की कार्यवाही में हो रही देरी पर भी चिंता जताते हुए, कहा कि लोकतंत्र से जुड़े मामलों में विलंब उचित नहीं है। ऐसा हुआ तो संस्थाओं पर लोगों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।

लोकतंत्र पर हमला बंद होना चाहिए

दमानिया ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल की समर्थक नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र की समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने उम्मीदवारों को एक विचारधारा, चुनाव चिह्न और उन पर भरोसा करके चुना था। ऐसे में बार-बार होने वाला दल-बदल मतदाताओं के विश्वास पर सीधा आघात है।

जनादेश के साथ हुआ घात

दमानिया ने आरोप लगाया कि जिन नेताओं को मतदाताओं ने शिंदे गुट के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनकर संसद भेजा वही यदि बाद में उसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो -यह मतदाताओं के जनादेश का अपमान है। दमानिया ने कहा कि इससे जनता का झ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है।

सुलग उठा कर्जमाफी आंदोलन!

पुलिस पर फेंके सुतली बम

हिंदमाता नेटवर्क @ बुलढाणा

महाराष्ट्र में किसानों की पूर्ण कर्जमाफी और विभिन्न कृषि मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पूर्व नेता और कद्दावर किसान नेता रविकांत तुपकर का आंदोलन अब बेहद उग्र और हिंसक मोड़ ले चुका है। तुपकर के अन्नत्याग आंदोलन का आज चौथा दिन है। भूख हड़ताल के कारण बुलढाणा में तुपकर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे उनके समर्थकों और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस आंदोलन की गूंज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक पहुंच गई है, जहां मंत्रालय के ठीक सामने हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रशासन द्वारा आंदोलन की अनदेखी किए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर बुलढाणा तक तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी है, जिससे पूरे राज्य का माहौल गरमा गया है।

मंत्रालय के सामने पेड़ पर चढ़ा कार्यकर्ता

गुरुवार को मुंबई में देश के सबसे सुरक्षित प्रशासनिक भवनों में से एक 'मंत्रालय' के ठीक सामने उस समय हड़कंप मच गया, जब रविकांत तुपकर का एक समर्थक सुरक्षा घेरे को तोड़कर वहां स्थित एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। इस कार्यकर्ता के हाथ में धागों से भरे बम (सुतली बम) का एक थैला था। जब नीचे तैनात पुलिसकर्मियों और दमकल कर्मियों ने उसे रोकने और नीचे उतारने का प्रयास किया, तो उसने पेड़ के ऊपर से ही पुलिस पर सुतली बम फेंकने शुरू कर दिए। इस अप्रत्याशित हमले से मंत्रालय परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई। बाद में उस कार्यकर्ता ने पेड़ पर ही खड़े होकर राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे बड़ी मशक्कत से हिरासत में लिया।

'बच्चों को पढ़ाएं या चुनाव ड्यूटी करें?'

शिक्षकों की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, फिलहाल कार्रवाई पर रोक

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की ड्यूटी न करने पर दर्ज हो रही एफआईआर से परेशान होकर, मुंबई शहर के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षकों का मुख्य सवाल है कि वे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं या चुनाव ड्यूटी करें। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने और गायब रहने के आरोप में, मुंबई के विभिन्न स्कूलों के 100 से अधिक शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षकों को दी राहत

इस मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड़ की पीठ ने, चुनाव आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों पर अगली सुनवाई तक कोई है। दंडात्मक कार्रवाई न करने का मौखिक आश्वासन दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 19 जून को तय की गई।

हिंदमाता एंकर: बीच पर सोने को मजबूर सैकड़ों लोग, छिड़ी गई बहस

'मुंबई में ऐसा पहले कभी नहीं देखा...'

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मायानगरी मुंबई में इन दिनों भीषण गर्मी, उमस और बिजली कटौती ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन तस्वीरों में दर्जनों लोग रात के अंधेरे में मुंबई के वसोर्वा बीच की रेत पर चादर बिछाकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि मुंबई शहर में रहने वाले गरीब तबके और झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों की उस मजबूरी को बयां करता है जो आसमान से बरसती आग और बिना बिजली की रातों में घुटने को मजबूर हैं।

मुख्य समस्या और कारण क्या है?

ये कोई अतिक्रमणकारी या बेघर लोग नहीं हैं, बल्कि वसोर्वा बीच से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित बस्तियों और झुग्गियों में रहने वाले नागरिक हैं। मुंबई में इस साल पड़ रही अप्रत्याशित गर्मी और चिपचिपी उमस ने घरों के भीतर रहना दुश्वार कर दिया है। इन झुग्गियों में एस्बेस्टस या टिन की छतें होती हैं जो दिनभर की तेज धूप में भट्टी की तरह तप जाती हैं। रात के समय भी ये छतें ठंडी नहीं होतीं। इसके ऊपर से बार-बार होने वाली बिजली कटौती ने समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। पंखे न चलने और वेंटिलेशन की भारी कमी के कारण इन छोटे-छोटे कमरों में सोना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में राहत की सांस लेने और समंदर की ठंडी हवाओं के सहारे अपनी रात काटने के लिए ये लोग परिवार सहित बीच पर आ जाते हैं। रात भर खुली हवा में सोने के बाद, सुबह होते ही ये सभी वापस अपने घरों और फिर अपने-अपने काम पर लौट जाते हैं।

रहने की जगह नहीं है, तो मुंबई छोड़ दें

वीडियो शेयर करने वाले एक एक्स यूजर ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। यूजर ने क्लिप के साथ कैप्शन में लिखा कि यह वीडियो वसोर्वा का है। हाल ही में भायंदर खाड़ी से भी ऐसा ही एक वीडियो देखा था। मैंने मुंबई में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अगर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो कृपया मुंबई छोड़ दें, लेकिन सार्वजनिक जगहों को इस तरह से खराब न करें। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अन्य यूजर ने भी दावा किया कि उसने बांद्रा के कार्टर रोड पर भी पिछली रात बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखा था। वहीं दूसरी ओर, एक बहुत बड़ा वर्ग इन लोगों के समर्थन में उतर आया है। सहानुभूति रखने वाले नागरिकों का कहना है कि ये वही लोग हैं जो दिन भर ओला-उबर चलाते हैं, घरों में काम करते हैं, और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके बिना मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से थम जाएगी। एक यूजर ने लिखा कि चिलचिलाती गर्मी में टिन की छतों के नीचे सोना किसी यातना से कम नहीं है। दिनभर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद अगर उन्हें चैन की नींद नहीं मिलेगी, तो वे अगले दिन शहर की सेवा कैसे करेंगे?

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इन तस्वीरों ने एक तीखी बहस छेड़ दी है। एक तरफ कुछ लोग इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। उनका तर्क है कि सार्वजनिक स्थानों का इस तरह से इस्तेमाल शहर की सुंदरता को खराब करता है। कुछ यूजर्स ने चिंता जताई है कि खुले मैदानों और बीच पर इस तरह सोने की आदत भविष्य में स्थायी अतिक्रमण और नई झुग्गियों का रूप ले सकती है।

शहरी बुनियादी ढांचे की विफलता

यह घटना केवल वसोर्वा बीच तक सीमित नहीं है। ऐसी ही तस्वीरें बांद्रा के कार्टर रोड और भायंदर खाड़ी से भी सामने आई हैं, जहां लोग फ्लाईओवरों के नीचे या खुले मैदानों में सोते देखे गए हैं। यह स्थिति मुंबई में किफायती आवास की भारी कमी और अनियंत्रित पलायन के कारण पैदा हुए बुनियादी ढांचे के चरमराते संकट को उजागर करती है।

प्रभाग समिती 'आय' कार्यालय, वसई
prabaagsamitie@gmail.com
ता. वसई, जि. पालघर पिन नं. ४०१ २०१

दूरध्वनी : २५०-२३०९०२०/२३२२२५८
रुग्णालय : २३२२१२०/२३२३३४३
फॅक्स : ०२०५-२३२२१२०
जा.क्र :ववि़शम/कर/३७६/२०२६-२७
दिनांक : १८/०६/२०२६

जाहिर नोटीस

वसई-विरार शहर महानगरपालिका सर्व नागरिकांना सुचित करण्यात येते की, खालील नमूद मिळकत धारकांनी मालमत्ता हस्तांतरण करणेकामी लेखी अर्ज तसेच कागदपत्रे प्रभाग समिती-आय कार्यालयात सादर केली आहेत. उक्त फेरफार प्रकरणी कोणतीही हरकत / तक्रार असल्यास त्यांनी कार्यालयात जाहीर नोटीस प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून ७ दिवसाच्या आत लेखी स्वरुपात कागदपत्रासह नोंदवावी. सदर बाबतीत कोणतीही हरकत / तक्रार न आल्यास कार्यालयामार्फत पुढील मालमत्ता हस्तांतरणाची कार्यवाही करण्यात येईल.

अ. क्र.	विभाग	मालमत्ता क्र.	ज्याचे नावे मालमत्ता आहे त्याचे म्हणजे विकणाऱ्या किंवा करदात्याचे नाव	खरेदीदाराचे किंवा अभिहस्तांकन करदात्याचे नाव
1.	वसई	VV09/6426	भिमाबाई गजानन पाटील	रमेश गजानन पाटील / रेखा सुरेश पाटील / मंदा ज्ञानेश्वर पाटील / अरुण गजानन पाटील
2.	वसई	VV01/172	फेलुबाई शावेर डीमेलो	लेस्ली झेवियर डिमेलो व आग्नेस राजन डिमेलो
3.	वसई	VV10/14569	मालती दिपक गोहिल रवि सोमा चव्हाण	मालती दिपक गोहिल
4.	सांडोर	SD02/751	झेवियर एलायस डिसोजा	जॉर्जीर्ना झेवियर डीसोजा
5.	वसई	VV09/120420/32	सुपर सटार डेव्हलपर्स	सिल्वेस्टर सेबेस्टियन मस्तान
6.	वसई	VV08/18057	नंद किशोर माशेलकर	प्रियांका प्रशांत पडवळ
7.	सांडोर (शुद्धपत्रिका)	SD02/466	राफायल दुमिंग सिरवेल	संदीप राफायल सिरवेल व रॉस्टन राफायल सिरवेल
8.	नायगाव	NG01/304/53	सुर्या बिल्डर्स	वामन वी नागवेकर
9.	वसई	VV09/20253/5	आरती गणेश हातोडे व गणेश प्रकाश हातोडे	आयवन सालोमन परेरा व अमिता आयवन परेरा
10.	वसई	VV09/20253/23	प्रीती महेश पवार	प्रकाश मतेस घोन्सालवीस व नीता प्रकाश घोन्सालविस
11.	वसई	VV02/20495	ईझाबेल चार्ल्स अंद्रादीस	ऑल्वीन चार्लस अंड्राडीस
12.	नायगांव	NG01/437/8	मे. साई प्रसाद कंस्ट्रक्शन कंपनी	प्रकाश हरिश्चंद्र वैती
13.	वडवली	VD01/733/2	अंड्रियन आय डिमेलो व योलाड मु डिमेलो	तेजस किशोरभाई झवेरी व श्वेता विनायक तांबे
14.	वसई	VV07/13827	टॉमस जोसेफ ब्रिटो	रेबेका सुरेश घोन्सालविस
15.	वसई	VV04/11691	नेस्टर कुटिन्हो	भरत जंयतीलाल मकवाणा
16.	वसई	VV18/18858	रामचंद्र भगवान काळे	मंगला सपन रंग
17.	वसई	VV01/475	अनंत के साधळे	नेहा जयदत्त मदभावीकर
18.	वसई	VV07/11825	फ्रान्सिस पोशान डायस	अजय फ्रान्सिस डायस व रोहन फ्रान्सिस डायस
19.	वसई	VV07/10316	प्रशांत मल्हारी चोपडे	कविता कन्नु खारवी
20.	वसई	VV06/14942	केदार रमाकांत हुदलीकर व विनया केदार हुदलीकर	विनया केदार हुदलीकर
21.	वसई	VV02/10020	संदिप दिनानाथ चौधरी	युफ्रेजिया संदिप चौधरी

सही/-
सहा. आयुक्त
प्रभाग समिती 'आय'
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

दैनिक हिंदमाता मिरर
पैनी नजर, पुख्ता खबर
ठाणे, शुक्रवार 19 जून, 2026
माइंड MIRROR

विचार प्रवाह

आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए, अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है।

- डेल कार्नेगी

संपादकीय

सुरक्षित सिरप

भारत में छोटे-मोटे रोगों के उपचार के लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाने की लोगों में आदत पायी जाती है। यह जाने बगैर कि घरेलू नीम-हकीमी जान को खतरे में भी डाल सकती है। भारत तथा कई अन्य देशों में देश में बने सिरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु से दवा उद्योग पर आंच आई थी। यही वजह है कि खांसी व अन्य दवाओं के सिरप की बिना डॉक्टर की पर्ची के बिक्री पर रोक लगाने का फैसला सरकार को लेना पड़ा है। निश्चय ही केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला सही समय पर लिया गया जरूरी कदम कहा जा सकता है। निस्संदेह, सरकार के इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा माना जाना चाहिए। हाल की कुछ दुखद घटनाओं के घातक परिणामों के मद्देनजर लोगों को हर खांसी-जुकाम आदि छोटे-मोटे रोगों के लिये खुद दवा लेने की आदत से परहेज करना चाहिए। दरअसल, भारत में लंबे समय से ऐसी धारणा रही है कि ये सिरप आदि दवाइयां मौसमी बीमारियों के लिये नुकसान-रहित होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में हुई दुखद घटनाओं ने इनके अंधाधुंध प्रयोग और दवा निर्माण से जुड़े कमजोर नियमन को ही उजागर किया है। सरकार को ये कदम अनेक दुखद घटनाओं के सामने आने के बाद उठाना पड़ा है, जब इन दवाओं के उत्पादन में गंभीर खामियां सामने आईं। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप लगाए गए थे कि गैम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून आदि देशों में दर्जनों बच्चों की मौत भारत में बने दूषित खांसी के सिरप के उपयोग से हुई थी। इतना ही नहीं, देश के भीतर भी दूषित दवाओं से जुड़ी मौतों की खबरों ने इन सिरपों की गुणवत्ता नियमन, परीक्षण और निगरानी पर गाहे-बगाहे सवाल उठाए हैं। निश्चित रूप से इन दुखद घटनाओं ने दुनिया भर में सस्ती दवाओं की आपूर्ति करने वाले भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान ही पहुंचाया है। सरकार की हालिया पहल को इसी दिशा में उठाया गए कदम के रूप में देखना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ कफ सिरप का ही नहीं है। आम भारतीयों की आदत में शुमार है कि लोग अक्सर खांसी-बुखार की दवाइयां यह जाने बगैर सेवन करते हैं कि उनमें क्या-क्या मिला है। यह भी कि इनके उपयोग से हमारे शरीर में क्या-क्या साइड-इफेक्ट हो सकते हैं। यह भी जानने की कोशिश नहीं होती है कि इन सिरप आदि को अन्य दवाओं के साथ लेने से क्या-क्या नकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे शरीर में हो सकती है। बहरहाल, अब जब सरकार ने तय कर दिया है कि अनुभवी डॉक्टर की सलाह से ही सिरप आदि खरीदे जा सकते हैं तो मरीजों के तिमारदार तय कर सकेंगे कि किस कंपनी की गुणवत्ता वाली दवा खरीदनी है। जिससे न केवल इलाज सही हो सकेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि मरीज के शरीर में कोई अन्य बीमारी छूट न जाए। लेकिन हकीकत यह भी है कि सिर्फ कठोर कानून बनाने मात्र से ही बेहतर परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते हैं। भारत में पहले से ही दवाइयों की बिक्री के नियमन से जुड़े कानूनों की कमी नहीं है। इसके बावजूद डॉक्टर की पर्ची पर ही उपलब्ध होने वाली दवाइयां अक्सर बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के ही आसानी से मेडिकल स्टोरों में मिल जाया करती हैं। दरअसल, असली चुनौती कानून का अनुपालन सख्ती से करने की होती है। जब तक देश में तमाम फार्मेसियों की नियमित जांच नहीं होती, कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान नहीं होता, तब नये नियम-कानून महज अच्छे इरादे वाले निर्देश मात्र बनकर रह जाएंगे। ऐसे में इस प्रयास का जमीनी असर बेहद कम ही रह पायेगा। वास्तव में देश में दवा उत्पादक इकाइयों की नियमित निगरानी, राज्यों में सशक्त ड्रग-कंट्रोल अथॉरिटी, नियमित गुणवत्ता जांच के अलावा जन चेतना अभियान चलाने की सख्त जरूरत है। लोगों को बिना डॉक्टर के परामर्श के दवा लेने के खतरों से अवगत कराना होगा। निस्संदेह, सरकार द्वारा चिकित्सक के परामर्श पर ही सिरप आदि की उपलब्धता से जुड़े नियम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किस सीमा तक एक जवाबदेह सिस्टम बना पाते हैं।

आज का इतिहास

■ 1996 - बौद्धिक संपदा कानून (आई.पी.आर.) पर चीन एवं संरा. अमेरिका में समझौते, प्रसिद्ध अंपायर डिकी बर्ड एम. सी.सी. की आजीवन सदस्यता से सम्मानित।

■ 1999 - कोलोन (जर्मनी) में समूह-8 की शिखर बैठक प्रारम्भ।

■ 2002 - पाकिस्तान के विदेश सचिव इनामुल हक को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया गया।

■ 2003 - फिनलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एनेली जाटिनमांकी ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

■ 2005 - फोर्ब्स पत्रिका ने ओफ्रा विनफे को दुनिया की सौ ताकतवर हस्तियों में पहला स्थान दिया।

■ 2006 - जापान ने उत्तरी कोरिया को परमाणु परीक्षण मामले पर चेतावनी दी।

■ 2007 - पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सूचना मंत्री के पद से मोहम्मद अली दुरानी को हटाया। विश्व में राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों की सूची में पाकिस्तान को 12वां स्थान प्राप्त हुआ।

■ 2008 -उत्तराखण्ड सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मनेरी व 380 मेगावाट की भैरोंधारी परियोजना को स्थगित किया। गाजापट्टी में हिंसक संघर्ष रोकने के लिए इजरायल व हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हुआ।

■ 1931 - सुदर्शन अग्रवाल - उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल

■ 1970 - राहुल गांधी - भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य।

■ 1871 - माधवराव सप्रे - राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिये समर्पित कार्यकर्ता थे।

■ 1948 - ओकरम इबोबी सिंह - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।

■ 2021 - गुरुप्रसाद मोहापात्रा - भारतीय आईएएस अधिकारी थे।

■ 2018 - नेरेला वेणु माधव - भारतीय मिमिक्री कलाकार थे।

■ 1981 - सुभाष मुखोपाध्याय - भारत के 'प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी' के जनक चिकित्सक व वैज्ञानिक थे।

मेघ दे, पानी दे

एल नीनो के बढ़ते खतरे के बीच सूखे की आशंका

कृषि नीतियों की कमजोरियां देश के सामने नई चुनौती

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि इस वर्ष मानसून उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस आशंका को स्वीकार कर चुके हैं। इसका कारण प्रशांत महासागर में सक्रिय हुआ गर्म जल प्रवाह है, जिसे 'एल नीनो' कहा जाता है। यह स्पेनिश शब्द है। करीब चार सौ वर्ष पहले पेरू के एक मछुआरे ने इस गर्म समुद्री धारा को पहचाना था। उसने देखा कि क्रिसमस के आसपास यह धारा सक्रिय होती है और मछलियां अपने स्थान बदलने लगती हैं। इसी कारण उसने इसे 'एल नीनो' अर्थात 'बाल यीशु' का नाम दिया। उस समय शायद उसे इसके दूरगामी प्रभावों का अंदाजा नहीं रहा होगा, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बाद में सिद्ध किया कि यह घटना दुनिया के कई हिस्सों के मौसम को प्रभावित करती है।

मानसून पर मंडराता खतरा

एल नीनो की सक्रियता के दो प्रमुख कालखंड माने जाते हैं। पहला जून से सितंबर और दूसरा नवंबर के बाद। भारत के लिए पहला कालखंड सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही दक्षिण-पश्चिम मानसून का समय है। यदि इसी दौरान एल नीनो सक्रिय हो जाए तो वर्षा पर गंभीर असर पड़ता है। इस वर्ष भी यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पहले उम्मीद थी कि एल नीनो अगस्त के बाद प्रभाव दिखाएगा, लेकिन इसके समय से पहले सक्रिय हो जाने से सूखे की आशंका बढ़ गई है। यदि ऐसा हुआ तो खेतों में ही नहीं, आम लोगों की आंखों में भी चिंता के बादल उमड़ेंगे।

शहरों तक पहुंचेगा असर

आमतौर पर शहरों के लोग टैंकरों और वैकल्पिक जल स्रोतों के सहारे पानी की कमी से किसी तरह निपट लेते हैं। इसलिए सूखे का असर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कम महसूस होता है। लेकिन इस बार स्थिति अलग हो सकती है। यदि व्यापक स्तर पर वर्षा की कमी हुई तो उसका प्रभाव केवल खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे आर्थिक ढांचे पर दिखाई देगा। पिछले कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मांग को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब शहरी आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही थी, तब ग्रामीण क्षेत्रों की खरीद क्षमता ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्व

छोटे शहरों और कस्बों के लोगों ने दोपहिया वाहनों, छोटी कारों और निवेश बाजारों में भागीदारी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति दी। यदि ग्रामीण क्षेत्र सूखे की मार झेलते हैं, तो इसका सीधा असर मांग पर पड़ेगा। परिणामस्वरूप शहरों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। पहले से महंगाई और आर्थिक दबाव झेल रहे शहरी नागरिकों को अब ग्रामीण संकट का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। इस तरह 'भारत' और 'इंडिया' के बीच दिखाई देने वाली आर्थिक दूरी एक अलग ही रूप में कम होती नजर आ सकती है।

सरकारी नीतियों पर सवाल

एक ओर सरकार एल नीनो के दुष्प्रभावों की चेतावनी दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का भारी भंडारण होने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया गया है कि इन फसलों की सरकारी खरीद में इस वर्ष 13 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। सरकार ने जितनी खरीद का लक्ष्य रखा था, उससे भी अधिक खरीद करनी पड़ी। सतही तौर पर यह उपलब्धि लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर समस्या छिपी हुई है।

गेहूं-चावल पर अत्यधिक निर्भरता

किसानों ने अन्य फसलों की तुलना में गेहूं और धान की खेती को अधिक प्राथमिकता दी है। इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकारी व्यवस्था में सबसे अधिक संरक्षण इन्हीं दो फसलों को मिलता है। जबकि अन्य फसलें भी इस योजना में शामिल हैं, लेकिन व्यवहार में सरकार का ध्यान मुख्य रूप से गेहूं और धान पर ही केंद्रित रहता है। यही कारण है कि किसान पानी की अत्यधिक खपत और मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की परवाह किए बिना इन फसलों की खेती करते हैं।

दलहन और तिलहन की उपेक्षा

यदि सरकारी प्रोत्साहन संतुलित हो तो किसान दलहन और तिलहन जैसी महत्वपूर्ण फसलों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की थी। लेकिन एक दशक बाद भी देश इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। आज भी खाद्य तेलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति दर्शाती है कि घोषित नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर मौजूद है।

कृषि नीति की दिशाहीनता

कृषि क्षेत्र में नीतिगत असंगति केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है। एक ओर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं जो उनके उपयोग को बढ़ावा देती हैं। परिणामस्वरूप यूरिया जैसे उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसके लिए सरकार को भारी सब्सिडी का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। यह स्थिति बताती है कि कृषि नीति में दीर्घकालिक दृष्टि और संतुलन की कमी बनी हुई है।

बढ़ेगा सरकारी दबाव

यदि एल नीनो के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, तो सरकार को किसानों और खेती दोनों को राहत देने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इससे राजकोषीय घाटा और बढ़ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी होती है और इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन जब अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हो, तब दूरदर्शी सुधार लागू किए जाने चाहिए। दुर्भाग्य से कई आवश्यक सुधार समय रहते नहीं किए गए।

चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल

पश्चिम एशिया के संघर्षों ने पहले ही कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे चालू खाते का घाटा बढ़ा है और विदेशी निवेश में भी कमी आई है। इन परिस्थितियों का असर रुपए की स्थिति पर भी पड़ा है। ऐसे समय में यदि एल नीनो के कारण कृषि संकट और गहरा होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर दोहरा दबाव आएगा। इस स्थिति में अच्छी वर्षा ही सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है।

सबकी एक ही प्रार्थना

आज परिस्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि धर्म, जाति और विचारधारा से परे हर व्यक्ति की इच्छा एक ही है-अच्छी बारिश हो। चाहे कोई अल्लाह से दुआ मांगे या राम-श्याम से प्रार्थना करे, हर जुबान पर एक ही पुकार होगी-मेघ बरसें, धरती भीगे और जीवन में फिर से हरियाली लौट आए।

गहलोत और पायलट की मुस्कान के पार कांग्रेस का सियासी सच

निरंजन परिहार
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

राजस्थान में कांग्रेसी राजनीति की उड़ान उलझन भरी है। बरसों सत्ता में रहने वाली ताकतवर कांग्रेस राजनीतिक धरातल पर कमजोर लगती है, तो कभी कभार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने की हुंकार भरती हुई भी दिखती है। इसीलिए अपने नेताओं में ताल मेल और मोलजोल भरी मुलाकातों की तस्वीरें उत्साह जगाती हैं, और होठों पर हंसी और चेहरों पर मुस्कान भरी हाथ मिलाते हुए तस्वीरें देखते ही कांग्रेसी चिहुंच उठते हैं। लेकिन राजस्थान की कांग्रेसी राजनीति के सारे सच समझने के लिए तस्वीरों के पार का सच समझने की जरूरत है। राजनीति में तस्वीरें अक्सर वही दिखाई जाती हैं, जिसे दिखाना जरूरी होता है। लेकिन राजनीति की असली कहानी उन तस्वीरों के पार होती है, जहां कैमरे की रोशनी नहीं पहुंचती। राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों

अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुस्कुराती तस्वीरें चर्चा में हैं। राहुल गांधी की कोटा यात्रा के दौरान दोनों नेताओं का आत्मीयता से हाथ मिलाना और चेहरे पर सहज मुस्कान लिए हंसते हुए दिखाई देना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहत और उत्साह का कारण बना। लेकिन राजनीति की तस्वीरों में दिखने वाली निकटता और राजनीतिक वास्तविकताओं की दूरी के बीच अक्सर लंबा फासला होता है, और उसी सच को समझने की जरूरत है।

दो धाराओं में बहती कांग्रेस

पिछले एक दशक से राजस्थान कांग्रेस दो समानांतर राजनीतिक धाराओं के बीच बह रही है। एक धारा अनुभव, संगठनात्मक कौशल और सत्ता संचालन की कला का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका चेहरा अशोक गहलोत हैं। दूसरी धारा महत्वाकांक्षा, नई पीढ़ी की राजनीति और भविष्य के नेतृत्व की आकांक्षा का प्रतीक है, जिसका नेतृत्व सचिन पायलट करते हैं। दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दोनों की अपनी ताकत है, दोनों का अपना जनाधार है और दोनों की राजनीतिक यात्रा का अंतिम पड़ाव सत्ता के शिखर तक पहुंचना ही है। राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई दोष नहीं होती। बल्कि यही वह ईंधन है, जिससे राजनीतिक यात्राएं आगे बढ़ती हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कोई नेता अपनी महत्वाकांक्षा को कितनी कुशलता से राजनीतिक रणनीति में बदल पाता है। अशोक गहलोत ने अपने 50 साल के लंबे अनुभव से राजनीति की यह ललित कला सिद्ध कर रखी है। और सचिन पायलट अभी अपने राजनीतिक भविष्य को उस मुकाम तक पहुंचाने के संघर्ष में हैं, जहां नेतृत्व केवल संभावना नहीं, बल्कि निर्विवाद स्वीकार्यता बन जाए।

ताकत भी, विडंबना भी

राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भी यही है और विडंबना भी। विडंबना इसलिए कि पार्टी का बड़ा हिस्सा दो खेमों में बंटा दिखाई देता है। ताकत इसलिए कि दोनों नेताओं की सक्रियता ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से जीवंत, जीवित और प्रासंगिक बनाए रखा है। बीजेपी के मजबूत संगठन और सत्ता की निरंतरता के बीच कांग्रेस यदि आज भी मुकाबले की स्थिति में दिखाई देती है, तो उसके पीछे इन दोनों नेताओं की निरंतर राजनीतिक सक्रियता की बड़ी भूमिका है। समस्या वहीं पैदा होती है, जहां व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षाएं सामूहिक संगठनात्मक लक्ष्यों से बड़ी दिखने लगती हैं। कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता की पीड़ा भी यही है। वह चाहता है कि गहलोत और पायलट साथ दिखें ही नहीं, साथ चलें भी। क्योंकि उसे मालूम है कि राजस्थान में कांग्रेस का पुनरुत्थान किसी एक नेता की ताकत से संभव नहीं है। इसके लिए दोनों धाराओं का संगम आवश्यक है।

उम्मीद और विश्वास का अंतर

यही कारण है कि जब-जब गहलोत और पायलट की मुलाकात होती है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद का वातावरण बनता है। लेकिन उम्मीद और विश्वास में अंतर होता है। उम्मीद तस्वीरों से पैदा हो जाती है, विश्वास व्यवहार से बनता है। और राजस्थान कांग्रेस अभी उस विश्वास की तलाश में है, जो केवल मंच साझा करने से नहीं, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं को साझा करने से पैदा होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अपने अपने गुट भी बनाने की फिराक में हैं। लेकिन यह भी एक राजनीतिक यथार्थ है कि राजस्थान कांग्रेस की असली धुरी अभी भी गहलोत और पायलट ही हैं। संगठन की कमान किसी के हाथ हो सकती है, लेकिन जनभावनाओं और राजनीतिक विमर्श का केंद्र वही नेता बनते हैं, जिनकी स्वीकार्यता प्रदेशव्यापी होती है। डोटासरा और जूली चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मगर स्वीकार्यता की प्रदेशव्यापी कसौटी पर आज भी कांग्रेस में अशोक गहलोत नंबर वन और पायलट नंबर दो हैं, और डोटासरा - जूली इन दोनों नेताओं का विकल्प नहीं बन सकते।

पद और प्रभाव की राजनीति

असल में, राजनीति केवल पद का खेल नहीं है। पद किसी को अधिकार दे सकते हैं, लेकिन प्रभाव नहीं। प्रभाव संघर्ष, स्वीकार्यता और जन विश्वास से पैदा होता है। डोटासरा और जूली पद के नेता हैं, कद के नहीं। मगर, गहलोत और पायलट दोनों ने अलग-अलग रास्तों से यह प्रभाव अर्जित किया है। इसलिए दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा केवल व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि दो राजनीतिक शैलियों, दो पीढ़ियों और दो दृष्टिकोणों की प्रतिस्पर्धा भी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी राजनीतिक सफलताएं प्रतिस्पर्धा से नहीं, समन्वय से जन्म लेती हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पार्टी है, जिससे कभी भी जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की असली चुनौती अपने भीतर वह विश्वास पैदा करना है, जो कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिला सके कि पार्टी का भविष्य व्यक्तिगत समीकरणों का बंधक नहीं बनेगा।

कांग्रेस की असली परीक्षा

राजस्थान की जनता भी अब केवल राजनीतिक संदेशों से संतुष्ट नहीं होती। वह राजनीतिक व्यवहार को देखती है, नेताओं के संबंधों को परखती है और उनके निर्णयों से निष्कर्ष निकालती है। इसलिए तस्वीरों में मुस्कान जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह राजनीतिक संदेश है, जो उन मुस्कानों के पीछे छिपा होता है। कांग्रेस के लिए आने वाला वक्त बेहद निर्णायक हैं। विधानसभा चुनाव में केवल दो साल बचे हैं। यदि गहलोत का अनुभव और पायलट की ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो पार्टी नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकती है। लेकिन यदि तस्वीरों की मुस्कानें केवल अवसरों की औपचारिकता बनी रहीं, तो कार्यकर्ताओं की उम्मीदें फिर निराशा में बदल सकती हैं। आखिरकार राजनीति में हाथ मिलाने से ज्यादा जरूरी दिलों का मिलना होता है। क्योंकि जब दिल मिलते हैं, तब संगठन मजबूत होते हैं। और जब संगठन मजबूत होते हैं, तभी जनता का विश्वास लौटता है। राजस्थान कांग्रेस की असली परीक्षा भी यही है कि वह तस्वीरों की दोस्ती को राजनीतिक एकजुटता में कितना बदल पाती है। बाकी तो खैर, तस्वीरें तो बेचारी कल भी खिंचती थीं, आज भी खिंच रही हैं और आगे भी खिंचती रहेंगी। मगर कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेसियों के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए।

प्रेरक प्रसंग

आंगन की चिड़िया

पड़ोस की नन्ही पिंकी आंगन में चावल बिखेरकर चिड़ियों को बुला रही थी। वह बार-बार कह रही थी, 'आ चिया, आ...'। खिड़की से यह दृश्य देख रही राशि मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसके मन में बचपन की यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे अपना वही पुराना आंगन याद आ गया, जहां वह भी हर सुबह चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। दादाजी उसे प्यार से 'आंगन की चिड़िया' कहते थे। जब कभी वह दाना डालने नहीं पहुंचती, तो दादाजी आवाज लगाते, 'राशि, चिड़ियों को दाना नहीं खिलाएगी?' दादी पढ़ाई की चिंता करतीं, लेकिन दादाजी कहते, 'अभी खेलने दो हमारी आंगन की चिड़िया को। आज वह अपने घर में थी, लेकिन मन मायके के उसी आंगन में भटक रहा था। कुछ दिन पहले ही वह मां से मिलकर लौटी थी। तभी पता चला था कि मां कई दिनों से बुखार में थीं। मां ने हमेशा की तरह उसे तसल्ली दे दी थी, पर बेटी का मन कहां मानने वाला था। मन बहलाने के लिए राशि ने अलमारी ठीक करनी शुरू की। सामने मां की दी हुई साड़ी दिखी। वह साड़ी मां ने अपने हाथों से काढ़ी थी। उसे छूते ही लगा जैसे मां ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। फिर उसे एक पुराना फोटो एलबम मिला। एलबम के पन्नों के साथ उसका बचपन भी खुलता चला गया। तस्वीरों में दादाजी, दादी, मां और पिताजी के साथ बीते सुनहरे दिन थे। एक तस्वीर में उसकी सालगिरह की वह फ्रॉक थी, जिसे मां ने रातभर जागकर सिला था। दूसरी तस्वीरों में छोटा भाई था, जिसके लिए मां ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी। पिताजी के जाने के बाद मां ने अकेले ही परिवार को संभाला। बेटे की पढ़ाई, उसकी इच्छाएं, उसका भविष्य-सब कुछ अपनी जरूरतों से ऊपर रखा। यहां तक कि उसकी मोटरसाइकिल के लिए अपनी चूड़ियां तक बेच दीं। लेकिन आज वही बेटा मां की दवाइयां लाना भूल जाता है और उनसे शिकायतें करता रहता है।

■ राशि को सबसे अधिक पीड़ा यही देती है कि मां अब भी बेटे का पक्ष छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उसने कई बार मां को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मां हर बार मुस्कुरा कर कह देतीं, 'बेटी के घर मां अच्छी नहीं लगती। फोन मिलाने पर मां ने जवाब नहीं दिया। शायद सो गई होंगी। एलबम बंद करते हुए राशि की आंखें नम थीं।

■ उसे लगा, वह भी कभी उस आंगन की चिड़िया थी, जो उड़कर दूर चली गई। अब मायका उसका अपना होकर भी पराया है। वह वहां सिर्फ मेहमान बनकर जा सकती है, क्योंकि समाज की नजर में बेटी चाहे जितना प्रेम करे, वह पराए घर की होती है, और बेटा शिकायतों के बावजूद अपने घर का। यही जीवन का सबसे कड़वा सच है।

राशिफल

मेष- आय में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। जल्दबाजी न करें। पुराना रोग उभर सकता है। योजना फलीभूत होगी। कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है।

वृषभ-पूजा-पाठ में मन लगेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी। जल्दबाजी से हानि संभव है। थकान रहेगी। कुसंगति से बचें। निवेश शुभ रहेगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

मिथुन- आय में निश्चितता रहेगी। शत्रुभय रहेगा। घर-परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। फालतू खर्च होगा। अपेक्षाकृत कार्यों में विलंब होगा।

कर्क- प्रेम-प्रसंग में जोखिम न लें। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें। शत्रु पस्त होंगे। विवाद में न पड़ें। अपेक्षाकृत कार्य समय पर होंगे। प्रसन्नता रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यस्तता रहेगी। प्रमाद न करें।

सिंह- परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है। समय पर कर्ज चुका पाएंगे। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न तथा संतुष्ट रहेंगे। निवेश शुभ फल देगा। घर-परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, ध्यान रखें।

कन्या-मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। समय की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें।

तुला-मेहनत अधिक व लाभ कम होगा। किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएं। शत्रुओं की पराजय होगी। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। आय में निश्चितता रहेगी। दूर से बुरी खबर मिल सकती है। दौड़धूप अधिक होगी। बेवजह तनाव रहेगा।

वृश्चिक- जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि होगी। निवेश लाभदायक रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश शुभ रहेगा। व्यस्तता रहेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

धनु- व्यापार मनोनुकूल लाभ देगा। जोखिम बिलकुल न लें। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बड़ा काम करने का मन बनेगा। झंझटों से दूर रहें। फालतू खर्च होगा।

मकर- बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। कारोबारी बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें। आशंका-कुशंका रहेगी। पुराना रोग उभर सकता है। लापरवाही न करें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

कुंभ- व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। आय होगी। फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें। बजट बिगड़ेगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी। लेन-देन में सावधानी रखें। अपरिचित व्यक्तियों पर अंधविश्वास न करें। संतुष्टि नहीं होगी।

मीन-उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ हो सकता है। संचित कोष में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, प्रयास करें। कारोबारी सौदे बड़े हो सकते हैं। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य प्रभावित होगा।

लोकसभा में इतिहास रचेगा एनडीए!

दो तिहाई आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा; अब तक कितने नंबर हुए

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

दो साल पहले बहुमत के आंकड़े से पीछे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए पिछले कुछ दिनों से लोकसभा से गुड न्यूज आ रही है। यहां एनडीए का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और अब इतिहास रचने के करीब है। पहली बार एनडीए दो तिहाई के आंकड़े के पास पहुंचता दिख रहा है। एनडीए के नंबर्स पिछले महीने तब बढ़ने शुरू हुए, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 15 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। हारते ही ममता की टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। पहले विधानसभा में 64 विधायक बागी हो गए तो फिर बारी आई लोकसभा और राज्यसभा की। राज्यसभा में कई सांसदों ने इस्तीफा दिया और फिर लोकसभा में 20 सांसदों ने काकोली घोष के नेतृत्व में बगावत का बिगुल फूंकते हुए नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने का ऐलान कर दिया। साथ ही, यह गुट लोकसभा में अलग बैठेगा और एनडीए को सपोर्ट करेगा।

टीएमसी के बाद अब उद्धव गुट की आई बारी

टीएमसी के बाद अब उद्धव गुट में बड़ी टूट हुई है और दो तिहाई सांसद बागी हो गए हैं। इन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके पत्र लिखा है कि अलग बैठने की व्यवस्था करवाई जाए। ये छह सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ विलय करके एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इन छह सांसदों के एनडीए को सपोर्ट करने के बाद सत्ता पक्ष के गठबंधन का आंकड़ा और बढ़ गया है। उद्धव की पार्टी में यह पहली बार टूट नहीं है। आज से चार साल पहले भी इसी समय शिवसेना में टूट हुई थी और एकनाथ शिंदे कई विधायक और सांसद के साथ अलग हो गए थे। अब एक बार फिर से उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट हो रही है।

दो साल पहले जीतीं 293 सीटें, अब बढ़ रहा आंकड़ा

दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 543 सदस्यीय लोकसभा में 362 सीटों के आसपास माना जाता है। एनडीए अभी इस आंकड़े से नीचे है, लेकिन सहयोगी दलों में लगातार इजाफा हो रहा है। दो साल पहले हुए 2024 लोकसभा चुनाव में NDA ने कुल 293 सीटें जीती थीं। हालांकि, चुनाव से पहले एनडीए का नारा अबकी बार 400 पार का था, लेकिन भाजपा को तब झटका लगा, जब वह महज 240 पर सिमट गई। एनडीए को बहुमत तो आया, लेकिन 293 सीटें ही हासिल हुईं। तब एनडीए के प्रमुख सहयोगियों में टीडीपी को 16 सीटें, जेडीयू को 12, शिवसेना को सात, एलजेपीआर को पांच सीटें शामिल थीं। सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से 21 ज्यादा थीं, लेकिन दो तिहाई से काफी दूर आंकड़ा था।

दो तिहाई के नजदीक कैसे जा रहा एनडीए

अभी एनडीए के पास 293 सीटें हैं और इसमें हाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में हुई टूट के बाद एनसीपीआई में हुई विलय के 20 सांसद जोड़ दें तो यह आंकड़ा बढ़कर 313 हो जाएगा। मॉनसून सत्र से ही एनसीपीआई एनडीए को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा, छह सांसद उद्धव गुट की शिवसेना यूबीटी के बागी हो गए हैं। ये भी एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। इन्हें मिलाकर आंकड़ा 319 हो रहा है। लेकिन अब भी यह दो तिहाई के आंकड़े से काफी दूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे एनडीए यह आंकड़ा पा सकता है। इसके पीछे कुछ और दल हैं। दरअसल, बीते दिन यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अटकलों को हवा दे दी कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो 25-26 सांसदों के आंकड़ा भी दे दिया। हालांकि, यह अभी बहुत शुरुआती बात है, लेकिन अगर जैसे टीएमसी और शिवसेना यूबीटी टूटी, वैसा कुछ सपा के साथ होता है तो एनडीए का आंकड़ा और बढ़ जाएगा। सपा के पास यूपी में 37 लोकसभा सांसद हैं। इसमें दो तिहाई का आंकड़ा 25 होता है। इसे मिला लें तो 345 के आसपास आंकड़ा पहुंच सकता है। हालांकि, यह इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सपा का साफ कहना है कि उनकी पार्टी एकजुट है और मजबूत बनी है। वहीं, इसके बाद भी संख्या लगभग 17 से कम रह जाती है। एनडीए अभी इस संख्या से नीचे है, लेकिन यदि और सहयोगी दलों का विस्तार होता है, कुछ विपक्षी सांसद पाला बदलते हैं या छोटे दल गठबंधन का समर्थन करते हैं, तो यह दूरी और कम हो सकती है। हालांकि फिलहाल एनडीए के पास औपचारिक रूप से दो-तिहाई बहुमत नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ते समर्थन और विपक्षी खेमे में हो रही टूट-फूट के कारण राजनीतिक गलियारों में इस संभावना पर चर्चा तेज हो गई है।

इतिहास में कभी भी दो तिहाई तक नहीं पहुंचा एनडीए

अगर इस बार दो तिहाई का आंकड़ा हासिल होता है तो यह इतिहास में पहली बार होगा, जब एनडीए इस उपलब्धि को हासिल करेगा। एनडीए का अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2019 लोकसभा चुनाव में रहा था, जब उसने 353 सीटें जीती थीं। इसमें भाजपा को 303 सीटें मिली थीं और सहयोगी दलों के साथ एनडीए 353 के आंकड़े तक पहुंचा था। यह दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी 362 सीटों से 9 सीट कम था। 2024 के चुनाव में एनडीए का आंकड़ा घटकर 293 सीटों पर आ गया। हालांकि, इस बार दो तिहाई के आंकड़े की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि अप्रैल महीने में सरकार परिसीमन संशोधन विधेयक लेकर आई थी, जो दो तिहाई नंबर न होने की वजह से पास नहीं हो सका था। सरकार का उद्देश्य इसे पास करवाना है। अगर यह पास होता है तो देशभर में लोकसभा में सीटें बढ़कर 850 हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए दो तिहाई नंबर्स की जरूरत होगी। अब अगर सरकार यह आंकड़ा जोड़-तोड़कर हासिल कर लेती है तो इसे जल्द ही फिर से संसद में पेश किया जा सकता है।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी

जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत, अब तक 60 लोगों से पूछताछ

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

राम मंदिर दानराशि में गड़बड़ी की जांच लगातार जारी है। एसआईटी ने लगातार चौथे दिन भी संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। गुरुवार को राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से पूछताछ की गई। एसआईटी ने पिछले तीन दिनों में 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। दान गणना प्रक्रिया, मंदिर से बैंक तक धनराशि को ले जाने की प्रक्रिया समझी गई। सीसीटीवी कैमरों की जांच हुई। जांच में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के भी सबूत मिले हैं। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। वे राम मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। जानकारी के अनुसार एसआईटी शुक्रवार को जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक की जांच में जो दोषी पाए गए हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।

पदाधिकारियों से की जा रही गहन पूछताछ

एसआईटी चंपत राय, गोपाल राव समेत राममंदिर ट्रस्ट के कई अन्य पदाधिकारियों व उनसे जुड़े लोगों से गहनता से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये लोग कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वहीं, दान के दिए गए रिकॉर्ड से भी एसआईटी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसमें भी कई चीजें अस्पष्ट हैं। इसलिए एसआईटी को जांच में अधिक समय लग रहा है। विशेष जांच दल ने पूछताछ के लिए करीब दो सौ लोगों की सूची तैयार की है। इनमें से सवा सौ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें से कुछ से कई बार पूछताछ की है।

अब तक की जांच में कई नामों का खुलासा, क्या दर्ज होगी एफआईआर

पकड़े गए पांच संदिग्धों से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। उनके पास से रकम भी बरामद हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों ने कई नामों का खुलासा किया है, जिनको इस खेल में शामिल बताया है। एसआईटी ने उनके बयानों की तस्दीक कर रही है। अब सवाल है कि क्या एसआईटी की जांच के बीच एफआईआर दर्ज की जाएगी या जांच पूरी होने के बाद। या केस दर्ज ही नहीं होगा...ये सवाल अभी भी बना हुआ है।

ममता को हाईकोर्ट से झटका

ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे विपक्ष के नेता

हिंदमाता नेटवर्क @ कोलकाता

विधानसभा से लेकर संसद तक बगावत झेल रहीं ममता बनर्जी को अब कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले ममता खेमे के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया।

कैसे शुरू हुआ विधानसभा का विवाद

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को साठ सीटें मिलीं, जिससे विपक्ष के नेता का पद उसी को मिलना था। लेकिन पार्टी में अंदरूनी कलह सामने आ गई। तृणमूल नेतृत्व ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने की सिफारिश स्पीकर को भेजी, पर ऋतब्रत बनर्जी सहित कई विधायकों ने दावा किया कि यह प्रस्ताव फर्जी है और उसमें चौदह विधायकों के हस्ताक्षर जाली हैं।

कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर उठाए थे सवाल

बुधवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पीकर के रुख पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले स्पीकर को सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। अदालत ने यह भी पूछा था कि क्या केवल जालसाजी के आरोपों के आधार पर मूल प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जा सकता है, और बिना पूरी जांच के स्पीकर कैसे बहुमत का फैसला कर सकते हैं।

ऋतब्रत ने ठोका अधिकार का दावा

आरोप लगने के बाद पार्टी ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीपान साहा को निष्कासित कर दिया। इसके बाद ऋतब्रत ने अड़तालीस नाराज विधायकों का समर्थन लेकर स्पीकर के समक्ष अपना दावा पेश किया। स्पीकर रथेंद्र बोस ने बहुमत के आधार पर ऋतब्रत के गुट को मान्यता देते हुए उन्हें विपक्ष का नेता घोषित कर दिया, जिसे अदालत ने अब सही ठहराया।

लोकसभा में भी बगावत ने बढ़ाई मुश्किल

इस फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी गुरुवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में विपक्ष के नेता के रूप में कामकाज संभाल पाएंगे। वहीं ममता बनर्जी के लिए संकट और गहरा गया है, क्योंकि विधानसभा में करीब साठ विधायक बागी गुट के साथ हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी तृणमूल के बीस सांसदों ने अलग होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे ममता के लिए दोनों सदनों में मोर्चा संभालना मुश्किल हो गया है।

2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल

समाजवादी पार्टी में फूट का मुद्दा या भाजपाई दांव-पेंच

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की विपक्षी सरकारों में आई दरार के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में भी समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि सपा से करीब तीस सांसद अलग हो सकते हैं। वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ ऐसी ही बात कही, हालांकि सफाई यह दी कि भाजपा फिलहाल किसी को अपने साथ लेने के मूड में नहीं है। सपा ने इन तमाम बातों को बेबुनियाद करार देते हुए पूरी तरह नकार दिया है।

राजभर-मौर्य के बयानों ने बढ़ाई सियासी गर्मी

राजभर ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखकर पार्टी के उन नेताओं की सूची सौंपी है जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने पिछली सपा सरकार पर घोटालों के आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के डर से पार्टी के अंदर खलबली मची है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी दोहराया कि अखिलेश यादव पार्टी के नियंत्रण में नहीं हैं और उनकी सरकार नहीं, बल्कि उनकी पार्टी ही पहले टूटेगी। उन्होंने साफ किया कि भाजपा कोई ऑपरेशन नहीं चला रही, बल्कि सपा अपने आप बिखर रही है।

अखिलेश यादव ने पलटवार किया, विपक्षी एकता पर जोर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि भाजपा का पुराना खेल है, पहले डराते हैं, फिर लालच देते हैं। उन्होंने कहा कि डरने वाला ही भागता है, मजबूत इरादे वाले विपक्षी साथी बने रहते हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा के ही बहुत से विधायक असंतुष्ट हैं और सही समय आने पर उनके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता का साथ है, इसलिए सपा मजबूती से खड़ी है और 2027 में जनादेश भी सपा के पक्ष में होगा।

सपा नेताओं ने कसा तंज, दावों को बताया मनगढ़ंत

पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राजभर और मौर्य जैसे लोग सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि सपा का एक-एक सिपाही अखिलेश यादव के साथ है और कोई टूट नहीं होने वाली। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविदास मेहरोत्रा ने इन दावों को झूठा प्रचार करार देते हुए कहा कि भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की अफवाहें फैला रही है।

क्या है इस सियासी खेल की असली परत?

माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के मजबूत प्रदर्शन के बाद भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि विशेषज्ञों की नजर में अभी सपा में कोई बड़े पैमाने पर बगावत के संकेत नहीं दिखते। हां, इतना जरूर है कि टीएमसी और शिवसेना की ताजा स्थितियों ने इन अटकलों को जरूर हवा दी है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यह सिर्फ एक मानसिक चाल है या कोई बड़ा राजनीतिक खेल, मगर पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत जरूर गरमाई है।

कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने कर दिया खेल, करवाई क्रॉस वोटिंग; जीत लीं 5 सीटें

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

कर्नाटक विधान परिषद (MLC) की सात सीटों के लिए गुरुवार को हुई वोटिंग के नतीजे सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने पांच सीटें जीत ली हैं, जबकि संख्या के हिसाब से चार पर जीत तय लग रही थी। एक अतिरिक्त सीट पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था और उसपर जीत हासिल की। वहीं, भाजपा ने भी दो सीटों पर विजय हासिल की है। वोटिंग में सभी 222 विधायकों ने अपने वोट डाले। डीके शिवकुमार ने बीजेपी संग खेल करते हुए भाजपा से निकाले गए तीन विधायकों में से दो एस टी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार को क्रॉस वोट करवा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवा दिए। वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों ने बताया कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। कर्नाटक विधानसभा के सदस्यों ने विधान सौध में हुए चुनाव में मतदान किया। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतगणना शाम पांच बजे शुरू हुई। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में कांग्रेस के थिप्पन्नप्पा कामकनूर, पी. वी. मोहन, बी. के. हरिप्रसाद (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष), शिवन्ना बी एस, और विनय कार्तिक प्रकाश तथा भाजपा के लिंगराज पाटिल और रघु आर और जद(एस) के गोविंदराजू शामिल हैं।

एस.टी. सोमशेखर ने पत्रकारों से बात करते हुए माना कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के हित में कांग्रेस के लिए वोट दिया। सोमशेखर ने कहा कि मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया। मैंने शुरू में यह तय नहीं किया था कि किस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना है। अहम बात यह है कि कौन आपसे संपर्क करता है। न तो बीजेपी और न ही जेडी(एस) ने मेरा समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कल मुझे फोन किया और रिसॉर्ट में होने वाली बैठक के लिए बुलाया, जिसमें मैं शामिल हुआ। यह चुनाव कराने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि विधान परिषद के सात सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। इनमें कांग्रेस के नसीर अहमद, टिप्पन्नाप्पा और बी. के. हरिप्रसाद, भाजपा के एन. नागराजू (एमटीबी), प्रताप एस. नायक के. और सुनील वल्लयापुर तथा जद(एस) के गोविंदराजू शामिल हैं। मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक शामिल हैं।

कम से कम 28 वोटों की थी जरूरत

चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 28 मतों की जरूरत थी। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर, कांग्रेस और भाजपा के क्रमशः चार और दो सीटें आसानी से जीतने की संभावना थीं, लेकिन कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत दर्ज कर ली। सातवीं सीट के लिए कड़ा मुकाबला था, क्योंकि कांग्रेस और JD(S) दोनों ने ही उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि यह सीट जीतने के लिए उनके पास जरूरी संख्या बल नहीं है।

अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया

सत्तारूढ़ कांग्रेस, भाजपा से निकाले गए विधायकों और निर्दलीय सदस्यों की मदद से सात में से पांच सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी। वहीं, जद(एस) अपने सहयोगी दल भाजपा की मदद से एक सीट जीतने की उम्मीद कर रहा है। भाजपा से निकाले गए तीन विधायकों में से दो - एस टी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार - ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न तो भाजपा और न ही जद(एस) ने वोट मांगने के लिए उनसे संपर्क किया, जबकि मुख्यमंत्री शिवकुमार ने उनसे संपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा।

कोई खास रणनीति नहीं अपनाई

इस बीच, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस बात को खारिज कर दिया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए कोई खास रणनीति अपनाई। साथ ही, उन्होंने विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा कथित तौर पर 'क्रॉस-वोटिंग' किए जाने की जानकारी होने से भी इनकार किया। मतदान के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने विधायकों से बातचीत की थी और यह सुनिश्चित किया कि पहली बार वोट देने वालों को मतदान प्रणाली के बारे में सही जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि मतदान संपन्न हो चुका है। हमने कोई खास रणनीति नहीं अपनाई। किसी रणनीति की जरूरत भी नहीं थी। विधायक समझदार और बुद्धिमान लोग हैं। वे जनता के प्रतिनिधि हैं... हमें कोई रणनीति बनाने की क्या जरूरत थी? 'क्रॉस-वोटिंग'' की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस और जद (एस) दोनों ने ही अपने विधायकों को शहर के बाहरी इलाकों में अलग-अलग रिजॉर्ट में ठहराया था।

कांग्रेस विधायकों वाले रिजॉर्ट में दिखे थे भाजपा से निकाले गए विधायक

सोमशेखर और हेब्बार बुधवार को उस रिजॉर्ट में नजर आए, जहां कांग्रेस विधायक डेरा डाले हुए थे। गुरुवार को भी वे कांग्रेस विधायकों के साथ देखे गए और शिवकुमार से भी मिले। हालांकि, भाजपा से निकाले गए एक और सदस्य बासनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी के निर्देशों के अनुसार वोट दिया, क्योंकि वह इसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने विपक्ष के नेता आर. अशोक से भी मुलाकात की। इस बीच, जद(एस) के वरिष्ठ विधायक जी.टी. देवेगौड़ा, जो कुछ समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, ने अलग से वोट डाला और पार्टी के दूसरे विधायकों के साथ मतदान करने के लिए नहीं आए, जिस कारण अटकलें शुरू हो गईं। देवेगौड़ा ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया।

इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका

झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी विजयी

हिंदमाता नेटवर्क @ रांची

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन को करारा झटका दिया है, क्योंकि चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन के ही कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। नाथवानी को अट्ठाईस वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को बीस वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम ने तीस वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जो पहले से ही तय मानी जा रही थी।

क्रॉस वोटिंग ने बदली चुनावी तस्वीर

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास इक्यासी सदस्यीय विधानसभा में चौबीस विधायक हैं, जबकि जीत के लिए अट्ठाईस वोटों की दरकार थी। नाथवानी को ठीक अट्ठाईस वोट मिले, यानी विपक्षी खेमे से उन्हें चार प्रथम वरीयता के वोट हासिल हुए। वहीं चुनाव में कुल तीन वोट अमान्य पाए गए, जिनमें एक कांग्रेस और दो भाजपा के थे। चुनाव अधिकारी ने पुष्टि की कि नाथवानी की जीत सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग का नतीजा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक होने के बावजूद वह दोनों सीटें नहीं बचा पाया।

चौथी बार राज्यसभा पहुंचे

जीत के बाद परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश लिखा। राज्यसभा सदस्य के रूप में चौथी बार सेवा का अवसर पाकर वे बेहद कृतज्ञ हैं। यह उनके लिए विशेष पल है क्योंकि झारखंड से उनका यह तीसरा कार्यकाल है। यहीं से सन दो हजार आठ में उनकी संसदीय यात्रा शुरू हुई थी और अपनी कर्मभूमि में लौटना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पूरे एनडीए नेतृत्व के साथ-साथ उन सभी विधायकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें वोट दिया।

इंडिया गठबंधन के लिए चेतावनी

इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि संख्याबल के बावजूद इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अब झारखंड में हुई क्रॉस वोटिंग ने विपक्षी दलों की आंतरिक खींचतान को उजागर किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी इस तरह की चालों से इंकार नहीं किया जा सकता। झारखंड का यह नतीजा एनडीए के लिए उत्साहवर्धक है तो इंडिया गठबंधन के लिए चिंता बढ़ाने वाला।

जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना

ईरान समझौता नेतन्याहू की हार और पीएम मोदी की विफलता

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में पाकिस्तान की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए झटका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगातार तुष्टिकरण करना शर्मनाक और राष्ट्रविरोधी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन ईरान के लिए कई उपलब्धियां लेकर आया है तो यह इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पराजय भी है।

4 सूत्रीय इस्लामाबाद समझौता

रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन अब आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। इस समझौते का नाम 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू)' रखा जाना ही इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रतिष्ठा और वैश्विक प्रभाव में नया उभार आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वही देश है जिसे नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद डॉ. मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंच पर लगभग अलग-थलग कर दिया था। रमेश ने दावा किया कि यह प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की दिशा और शैली दोनों के लिए एक गंभीर झटका है।

आने वाले 60 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण

कांग्रेस नेता ने कहा कि पाकिस्तान अब पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक और सुरक्षा संरचना में पहले से कहीं अधिक गहराई से शामिल हो चुका है, जिसके भारत के लिए गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। रमेश ने कहा कि यदि यह एमओयू अपनी भावना और शब्दों, दोनों के अनुरूप लागू होता है, तो यह एक बड़ी प्रगति होगी। लेकिन इसमें दोनों पक्षों के लिए 'मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग' (गलतफहमी का समझौता) बन जाने की भी संभावना है। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि आने वाले 60 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

एमओयू स्वयं ईरान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह एमओयू स्वयं ईरान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कुछ हद तक अप्रत्याशित उपलब्धियां लेकर आया है। ईरान ने अपनी दृढ़ता और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया है। जिन जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) देशों ने ईरान के जवाबी हमलों का पूरा भार झेला है, उन्होंने इस एमओयू का सतर्कता के साथ स्वागत किया है। लेकिन वे निस्संदेह अन्य देशों के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करेंगे। उनके मुताबिक, यह एमओयू इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्पष्ट पराजय है, हालांकि वह अब भी विभिन्न तरीकों से इसे विफल कर सकते हैं। रमेश ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ चुके हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से उनके प्रति अपनी नाराजगी और निराशा व्यक्त की है।

चंदा चोरी जांच के बीच अयोध्या पहुंच रहे सीएम योगी

मंच पर नहीं दिखेंगे चंपत राय

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल शुक्रवार को अयोध्या दौरा है। चंदा चोरी के मामले की जांच के बीच इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है, उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चंपत राय की बजाय उनके प्रतिनिधि को शामिल करने की बात कही गई है। यानी प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ होने वाले कार्यक्रमों और मंच पर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कोई और करता दिखाई देगा। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या आगमन और राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों के लिए जो आधिकारिक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, उसमें ट्रस्ट की ओर से चंपत राय के बजाय उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी की बात कही गई है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार चंपत राय का नाम सूची में नहीं होने से चर्चाएं तेज हो गई हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक, चंपत राय उन चेहरों में रहे हैं, जिन्हें अयोध्या की राजनीति और राम मंदिर की पूरी कहानी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते वे लंबे समय से मंदिर से जुड़े प्रशासनिक और सार्वजनिक मामलों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि चंपत राय हमेशा मंच और कैमरों के सामने रहने वाले नेताओं में नहीं रहे। कई मौकों पर मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के दौरान ट्रस्ट की ओर से दूसरे पदाधिकारी भी दिखाई देते रहे हैं। दरअसल, इस प्रोटोकॉल को ऐसे समय में देखा जा रहा है, जब हाल के दिनों में चंपत राय का नाम एक अन्य वजह से भी चर्चा में रहा है।

करीब 7:30 घंटे तक अयोध्या और गोंडा में रहेंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को अयोध्या और गोंडा के दौरे पर रहेंगे। उनका कार्यक्रम सुबह 10:35 बजे अयोध्या जिले की रुदौली विधानसभा स्थित मां कामाख्या धाम हेलीपैड पर पहुंचने के साथ शुरू होगा। यहां वे मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसी के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:05 बजे गोंडा के लिए रवाना होंगे। गोंडा में आयुक्त सभागार में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 2:40 बजे गोंडा से अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री 3 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन करेंगे और फिर राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर मनिराम दास छावनी पहुंचकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे।

यूपी बोर्ड की बड़ी कार्रवाईः 465 विद्यालयों की मान्यता रद्द

प्रयागराज के 25 स्कूलों पर भी गिरी गाज

हिंदमाता नेटवर्क @ प्रयागराज

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रदेश के 465 मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। इस बड़ी कार्रवाई में प्रयागराज जिले के 25 विद्यालय भी शामिल हैं। बोर्ड की जांच में सामने आया कि इन विद्यालयों से पिछले दो शैक्षणिक सत्रों के दौरान एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हुआ, जिससे इनके वास्तविक संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार मान्यता निरस्त किए गए विद्यालय उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय मान्यता नियमावली के तहत मान्यता प्राप्त थे। हालांकि शासन और परिषद स्तर पर कराई गई समीक्षा एवं आकस्मिक जांच में पाया गया कि संबंधित विद्यालय निर्धारित मानकों और अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। कई विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां नगण्य थीं, जबकि कुछ संस्थानों का संचालन केवल कागजों तक सीमित होने की आशंका भी व्यक्त की गई। परिषद ने कार्रवाई से पहले सभी संबंधित विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। विद्यालय प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद परिषद ने नियमावली के प्रावधानों के तहत उनकी मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया। सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों की मान्यता निरस्त की गई है, वे अब किसी भी कक्षा में नए विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनके समायोजन की व्यवस्था की जाए। प्रयागराज में 25 विद्यालयों की मान्यता समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं अभिभावकों और छात्रों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि प्रभावित विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि बोर्ड की यह कार्रवाई केवल शुरूआत है। यदि जिले और प्रदेश में नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए तो शिक्षा के नाम पर चल रहे निष्क्रिय और नियमविरुद्ध संस्थानों पर और अधिक प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

शॉर्ट स्टोरी

2 लाख रुपए लेकर लौट रहे युवक का कत्ल, हत्या का शक

हिंदमाता नेटवर्क @ समस्तीपुर

बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ समस्तीपुर-पटना मुख्य मार्ग एनएच 28 को जाम कर दिया और सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के मुताबिक, एनएच 28 पर जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। यह घटना ताजपुर थाना क्षेत्र के हरपुर भिंडी गांव की है। मृतक की पहचान कुशेश्वर राय के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार कुशेश्वर राय ने कुछ दिन पहले अपनी जमीन बेची थी। खरीदार ने पूरी रकम का भुगतान नहीं किया था। बुधवार को उन्हें बकाया दो लाख रुपए मिले थे और वह रकम लेकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि घटनास्थल से रुपए वाला बैग गायब था। उनका आरोप है कि पहले कुशेश्वर राय के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उन्हें जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गई। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर समस्तीपुर-पटना-मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग एनएच 28 को जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान टायर जलाकर आगजनी की गई, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

पंचायत में पंच के मुंह खोलने पर हुई थी हत्या, मुखिया समेत 8 को उम्रकैद

हिंदमाता नेटवर्क @ पूर्णिया

पूर्णिया जिले के बहुचर्चित ताराबाड़ी डबल मर्डर केस में करीब चार वर्ष बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ताराबाड़ी पंचायत के वर्तमान मुखिया एजाज अंजुम, सरपंच गुलाम सरवर उर्फ शौकत समेत आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देशमुख की अदालत ने मंगलवार को सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया। अदालत ने सभी दोषियों पर 23-23 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। सजा पाने वालों में वर्तमान मुखिया एजाज अंजुम, सरपंच गुलाम सरवर उर्फ शौकत, वार्ड सदस्य हसनैन, वार्ड सदस्य मोजिबुर रहमान उर्फ ललटू, अंजुम आदिल, अकील अहमद, जक्की अहमद और मोहम्मद जफर शामिल हैं। इस हत्याकांड के पीछे पंचायत की राजनीति और वर्चस्व की लड़ाई बताई जाती है। जानकारी के अनुसार, ताराबाड़ी पंचायत से शाहबाज आलम पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए थे। चुनाव जीतने के बाद वह गांव की छोटी-बड़ी पंचायती में सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे। ग्रामीणों के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही थी। बताया जाता है कि कई मामलों में शाहबाज आलम पंचायती के दौरान मुखिया और सरपंच के फैसलों पर सवाल उठाते थे और उन्हें खुलकर चुनौती देते थे। पंचायत में उनका हस्तक्षेप और बढ़ता प्रभाव मुखिया और सरपंच को नागवार गुजरने लगा था। इसी विवाद ने धीरे-धीरे गहरी रंजिश का रूप ले लिया। बताया जाता है कि 28 जून 2022 को एक पंचायती के बहाने शाहबाज आलम को बुलाया गया। शाहबाज आलम अपने सहयोगी मुनाजिर आलम के साथ पंचायती में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान ताराबाड़ी हाट के समीप पहले से घात लगाए 15 से 20 हमलावरों ने दोनों को घेर लिया। इसके बाद दोनों को खदेड़-खदेड़कर तलवार, लोहे की रॉड और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया गया।

वक्फ संपत्ति पर फर्जीवाड़ा कर कब्जा करने का आरोपी गिरफ्तार

हिंदमाता नेटवर्क @ आगरा

वाराणसी कमिश्नरेट की चौक थाना पुलिस ने वक्फ संपत्ति पर धोखाधड़ी कर कब्जा करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मो। आजम (48) पुत्र शौकत अली, निवासी शेख सलीम फाटक, नई सड़क, थाना चेतगंज के रूप में हुई है।

क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, मामला वक्फ नंबर-294 (उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) की संपत्ति से जुड़ा है। आरोप है कि काजीपुरा कलां स्थित वक्फ की जमीन एवं भवनों के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर अवैध तरीके से नामांतरण और कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में चौक थाने में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मो। आजम को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में वक्फ संपत्ति से जुड़े अन्य तथ्यों की भी गहन जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ-कानपुर के बीच चलेगी रैपिड रेल

आउटर रिंग रोड भी बनेगा, ये है प्लान

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ-कानपुर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि लखनऊ और कानपुर को जोड़ने के लिए उन्नाव होते हुए रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन के लिए आउटर रिंग रोड भी बनने वाला है। इससे क्षेत्र में तेज विकास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जून को उन्नाव में 101 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 570 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अब उन्नाव को लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल कर लिया गया है। लखनऊ का विकास अब सिर्फ हजरतगंज जैसे इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विकास उन्नाव तक पहुंचेगा और कानपुर की ओर बढ़ेगा।

दो नए पुल और रैपिड रेल की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने के प्रस्ताव पहले ही मंजूर हो चुके हैं। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की तरह लखनऊ से कानपुर (उन्नाव होते हुए) रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र के चारों ओर एक आउटर रिंग रोड बनेगा। यह रोड लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को जोड़ेगा। इससे बड़ा विकास क्लस्टर बनेगा और सभी इलाकों में समान विकास होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्नाव में रक्षा निर्माण गलियारे (डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर) और एक नए औद्योगिक क्लस्टर के लिए करीब 700 एकड़ जमीन तैयार कर ली गई है। यहां नई कंपनियां आएंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार अगले 100 साल का सोचकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह उन्नाव को जोड़ता है और पूरी तरह विश्व स्तर का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के मामले में देश में आगे है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास का पूरा श्रेय जनता को जाता है, क्योंकि लोग विकास की सोच रखने वाली सरकार चुन रहे हैं। उन्होंने पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कुछ नेता सिर्फ अपने इलाके को ही राज्य मानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा घर उत्तर प्रदेश है और राज्य के 25 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं। उनकी भलाई और तरक्की के लिए काम करना हमारा मिशन है।

लाश को तो बख्श देते!

अस्पताल में शव के कानों से खींच लिए कुंडल

हिंदमाता नेटवर्क @ बदायूं

बदायूं जिला अस्पताल में 17 जून की शाम संविदा सफाईकर्मी वीरू ने इलाज के दौरान दम तोड़ने वाली दातागंज निवासी मृत महिला के कानों से कुंडल निकाल लिए। परिजनों का ध्यान शव को वाहन में रखने की व्यवस्थाओं में लगा होने का फायदा उठाकर यह चोरी की गई। परिजनों द्वारा शक होने पर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई जिसमें युवक की यह शर्मनाक हरकत साफ नजर आई। इसके बाद परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी और उसके पास से चोरी हुए कुंडल बरामद कर लिए गए।

अस्पताल प्रशासन ने की तुरंत कार्रवाई

जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ। अमित वार्ष्णेय ने बताया कि सीसीटीवी में कैद आरोपी युवक ठेकेदार के अधीन काम करने वाला सफाईकर्मी है। घटना की जानकारी मिलते ही सुपरवाइजर को निर्देश देकर आरोपी को तत्काल कार्य से हटा दिया गया है। परिजनों का सामान बरामद होने के कारण उन्होंने अस्पताल प्रशासन को कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परिजनों की व्यवस्था का उठाया फायदा

दातागंज कस्बे की रहने वाली महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अस्पताल परिसर में तैनात सफाईकर्मी वीरू ने इस घोर संवेदनहीन वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की सजगता से सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पूरा सच सामने आ गया।

रिजल्ट के लिए उत्सुक थी नीट छात्रा, मां ने खोला कमरा, लटकी मिली बेटी

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा ने नीट परीक्षा दी थी। परीक्षा रद्द होने की वजह से वह अवसाद में चल रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मूल रूप से बिहार के पटना निवासी रंजीत यादव रेलवे में टीटी के पद पर तैनात हैं। वह अपने परिवार के साथ रेलवे कॉलोनी, ऐशबाग में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी शिवानी यादव (17) ने 12वीं पास की थी। इसके बाद उसने नीट की परीक्षा दी थी। उसका पेपर काफी अच्छा हुआ था, लेकिन परीक्षा रद्द होने की वजह से वह अवसाद में चल रही थी।

दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकती मिली

बुधवार सुबह शिवानी अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली। सुबह उसकी मां कमरे में बुलाने पहुंचीं। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को आवाज लगाई। आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग पहुंचे। दरवाजा खोला गया तो शिवानी दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी मिली। बाजारखाला इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि शिवानी ने इंटरमीडिएट के बाद नीट के लिए आवेदन किया था। उसकी परीक्षा 21 जून को होनी थी।

चारपाई पर सो रहे पिता पर बेटे ने किया कुल्हाड़ी से हमला

सिर-गर्दन पर 7-8 वार, मौके पर ही मौत

हिंदमाता नेटवर्क @ अयोध्या

जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में बुधवार देर रात एक युवक ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब पिता घर के बाहर चारपाई पर गहरी नींद में सो रहे थे। सिर और गर्दन पर लगातार कई वार किए जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गांव निवासी ब्रह्मदेव कन्नौजिया (55) रात में भोजन करने के बाद घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब दो से ढाई बजे के बीच उनके छोटे बेटे गोलू कन्नौजिया ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने सिर और गर्दन पर सात से आठ वार किए, जिससे ब्रह्मदेव ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के दौरान हुई आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ हालत में ब्रह्मदेव को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। रात करीब तीन बजे प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रेम प्रसंग टूटने के बाद बदल गया था व्यवहार

ग्रामीणों के अनुसार गोलू दो भाइयों में छोटा है। बताया जा रहा है कि उसका गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। युवती की शादी कुछ समय पहले दूसरे स्थान पर हो जाने के बाद से वह मानसिक तनाव में रहने लगा था। ग्रामीणों का कहना है कि उसके व्यवहार में भी असामान्य परिवर्तन देखने को मिल रहा था।

पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहा था फर्जी इंस्पेक्टर

पूछताछ में खुली पोल

हिंदमाता नेटवर्क @ मिर्जापुर

मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को बुधवार को पकड़ लिया गया। वर्दी पर स्टार लगा होने के बावजूद उसके हावभाव और गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर मौजूद लोगों ने उससे पूछताछ की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे शहर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया।

वर्दी पर स्टार देखकर हुआ शक

बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहा था। उसकी वर्दी पर एक स्टार भी लगा हुआ था, जिससे वह खुद को पुलिस विभाग का अधिकारी दिखाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि उसकी बातचीत और व्यवहार से लोगों को संदेह हुआ। पूछताछ के दौरान वह अपनी पहचान और तैनाती को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। सूत्रों के अनुसार, यदि जांच में व्यक्ति के फर्जी पुलिसकर्मी होने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ वर्दी का दुरुपयोग, प्रतिरूपण और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

खुद को महिला थाना में तैनात सिपाही बताया

मामले की सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पूछताछ में उसने अपना नाम शिवलाल पाल तथा निवासी प्रयागराज बताया। उसने पुलिस को बताया कि वह महिला थाना में ड्यूटी करने के लिए आया है, लेकिन वह अपनी नियुक्ति, पदस्थापना और विभागीय पहचान से संबंधित कोई ठोस दस्तावेज नहीं दिखा सका। प्रारंभिक जांच में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी वास्तव में पुलिस विभाग से जुड़ा है या नहीं।

कौन था भरत तिवारी? थानेदार पर पिस्टल तानने के बाद हुआ एनकाउंटर

हिंदमाता नेटवर्क @ भोजपुर

बिहार के भोजपुर जिले में बिलौटी गांव है। इसी गांव के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है, वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजन इसे प्लान्ड मर्डर बता रहे हैं। भरत की मां आशा देवी ने पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आशा देवी का कहना है कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे पुलिस और एसटीएफ की टीम उनके घर पहुंची थी। उनके अनुसार, जवानों ने जबरन घर का दरवाजा खुलवाया और परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार को धमकाते हुए कहा था कि यदि भरत सामने नहीं आया तो पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आशा देवी का दावा है कि उनके बेटे को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई और बाद में उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। उसकी हत्या हुई है। मृतक की मां के अनुसार, भरत भूषण तिवारी गांव में बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था। गांव के पास बने फैन (जल निकासी मार्ग) के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा था, जिससे लोगों की जमीन और मकानों पर खतरा मंडरा रहा था। भरत पिछले एक महीने से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इस समस्या के समाधान और मिट्टी भराई की मांग कर रहा था, लेकिन उसकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि वह समाजसेवा से जुड़ा हुआ था और गांव की समस्याओं को लेकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहता था। आशा देवी ने बताया कि भरत बीएससी फाइनल वर्ष का छात्र था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उन्होंने पुलिस के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें भरत को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है।

हिंदमाता एंकरः सपा के अधिकांश सांसद पहली बार जीतकर संसद पहुंचे हैं और उनकी राजनीतिक पहचान सीधे अखिलेश यादव और सपा के चुनावी प्रतीक से जुड़ी हुई है

समाजवादी पार्टी का ममता और उद्धव की पार्टी जैसा हश्र होना इसलिए मुश्किल है!

हिंदमाता संवाददाता @ लखनऊ

ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) में टूट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को लेकर नए सियासी दावे किए जा रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। ओमप्रकाश राजभर और केशव मौर्य के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में भी वैसी ही टूट संभव है जैसी महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसदों ने अपना अलग गुट बना लिया है। हालांकि, मौजूदा राजनीतिक हालात और संसदीय गणित को देखें तो समाजवादी पार्टी में लोकसभा सांसदों की बड़ी टूट की संभावना बेहद कठिन नजर आती है। यही वजह है कि राजभर के दावे की हवा सपा के दो सांसदों ने निकाल दी है।

राजभर और केशव मौर्य का दावा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को कहा कि बहुत जल्द सपा में भी टूट होने जा रही है। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने उन सांसदों का नाम भी दिया है, जो भाजपा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं गुरुवार को दोबारा से राजभर ने कहा कि सपा के बागियों का नेतृत्व 'बागी बलिया' का लाल करेगा। इस तरह से उनका इशारा सपा सांसद सनातन पांडेय के ऊपर था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा के 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे हैं। हमें पता है कि 2027 चुनाव के बाद वो खुद ही टूटकर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा का संचालन, अखिलेश की साइकिल नहीं कर सकती है। वो साइकिल सैफई जा सकती है सत्ता के गलियारे में नहीं चल सकती है। इस तरह राजभर के बाद केशव मौर्य ने साफ कह दिया है कि सपा के सांसद बीजेपी के संपर्क में है।

सपा में टूट क्यों आसान नहीं है

अखिलेश यादव को भले ही सियासत विरासत में मिली है, लेकिन 2024 में पार्टी को कमबैक कराकर अपना लोहा मनवा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह जीत केवल सपा के संगठनात्मक नहीं थी, बल्कि अखिलेश यादव के नेतृत्व की भी बड़ी राजनीतिक स्वीकृति मानी गई। सपा के अधिकांश सांसद पहली बार जीतकर संसद पहुंचे हैं और उनकी राजनीतिक पहचान सीधे अखिलेश यादव और सपा के चुनावी प्रतीक से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि सांसदों के बड़े समूह के एक साथ अलग होने की संभावना सीमित दिखाई देती है।

ममता-उद्धव से अखिलेश कितने अलग

शिवसेना (यूबीटी) और टीएमसी के उदाहरण अलग थे। टीएमसी की टूट की बड़ी वजह बंगाल में सत्ता परिवर्तन था। ममता बनर्जी की सत्ता से बाहर होते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। इसके अलावा टीएमसी के ज्यादातर बागी सांसदों की नाराजगी अभिषेक बनर्जी को लेकर थी। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) में टूट की बड़ी वजह संख्या का कम होना। उद्धव के 9 लोकसभा सांसद थे, जिनमें से 6 सांसद बागी हुए हैं और वे एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। एकनाथ शिंदे पहले उद्धव के साथ रह चुके हैं और 2022 में बगावत कर ही सत्ता में आए थे।

राजभर-केशव के बयान रणनीति का हिस्सा

ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य के बयान सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दल विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी खुद को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य चुनौती के रूप में स्थापित करना चाहती है। ऐसे में राजभर और केशव सपा के भीतर असंतोष की चर्चाएं राजनीतिक दबाव बनाने का माध्यम भी हो सकती हैं।

सऊदी अरब ने वर्क वीजा को लेकर बदले नियम

भारतीय कामगारों पर पड़ेगा असर

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

सऊदी अरब में वर्क वीजा को लेकर अहम बदलाव किया गया है। देश के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के किवा प्लेटफॉर्म ने बताया कि सऊदी अरब ने वर्क परमिट में बड़ा बदलाव करते हुए नई शुरू हुई कंपनियों के लिए तुरंत मिलने वाले वर्क वीजा की अधिकतम संख्या घटाकर 5 कर दी है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और लेबर मार्केट के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कीवा ने बताया कि जो कंपनियां 2 साल से कम समय से चल रही हैं, वे ज्यादा से ज्यादा 5 इंस्टेंट वीजा के लिए ही पात्र होंगी। जबकि 2 साल से अधिक पुरानी कंपनियों के लिए यह सीमा 50 वीजा तक हो सकती है, चाहे वे एक ही बार में आवेदन कर लें या एक ही हफ्ते में कई बार आवेदन करें। उसने आगे बताया कि एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम में शामिल और जरूरी शर्तें पूरी करने वाली कंपनियों को शुरुआत में 2 ही वीजा मिलेंगे। सऊदीकरण की दरें बढ़ाने की सूरत में उन्हें और वीजा मिल सकेंगे।

नए बदलाव से क्या पड़ेगा असर

कहा जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के आने से भारतीय कंपनियों और भारतीय कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। सऊदी अरब में विदेशी कर्मचारियों में बड़ी संख्या भारतीयों की है। अब नई कंपनियों के लिए तुरंत जारी होने वाले वीजी की संख्या सीमित कर दिए जाने से नई कंपनियों या स्टार्टअप्स में शामिल होने के इच्छुक प्रोफेशनल्स की भर्ती की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। यही नहीं प्रोफेशनल्स अब इन नई कंपनियों के साथ काम करने की जगह स्थापित यानी 2 साल से अधिक पुरानी कंपनियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। पुरानी कंपनियों के पास वीजा कोटा अधिक होता है और वे 50 तक वीजा अप्लाई कर सकती हैं।

हर कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

कीवा ने विदेश से गैर-सऊदी कर्मचारियों को भर्ती करने को लेकर 10 तरह की शर्तें भी तैयार की हैं। इन 10 शर्तों में शामिल हैं- बिजनेस का स्टेटस एक्टिव होने के साथ-साथ कर्मचारियों के पास वैध वर्क परमिट और वैध कमर्शियल रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा मीडियम ग्रीन कैटेगरी या उससे ऊपर की कैटेगरी में रहकर सऊदीकरण की शर्तें पूरी करना होगा। साथ ही वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (वेतन सुरक्षा प्रणाली) का पालन करना, और अब्शेर या मुकीम जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी रखी गई है, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए सालाना सेल्फ-असेसमेंट करने के नियमों का पालन करना होगा।

खुलने जा रहा है होर्मुज

भारत में तेल-गैस की सप्लाई कब तक होगी सामान्य

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले, होर्मुज के बाहर लगाई गई अमेरिकी नाकाबंदी हटाई जाएगी। इसके बाद ईरान समुद्र के भीतर बिछाए गए बारूदी सुरंगों (माइंस) को साफ करेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि होर्मुज के रास्ते भारत को तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से कब तक बहाल हो पाएगी। भारत अपने कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते प्राप्त करता है। वहीं, भारत के लिए आयातित एलएनजी (प्राकृतिक गैस) का बड़ा हिस्सा कतर से आता है, और कतर भी होर्मुज के रास्ते ही गैस की आपूर्ति करता है।

ईरान खुद तेल बेचने की तैयारी में

अमेरिका के साथ डील पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। यानी अब ईरान खुलकर तेल बेच सकता है। ईरान के पास फिलहाल लगभग 100 करोड़ बैरल तेल का भंडार मौजूद है, जिसे वह बाजार में बेचने के लिए उतार सकता है। अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत सीधे ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहा था। प्रतिबंध हटने के बाद भारत के लिए ईरान से तेल खरीदने का रास्ता खुल गया है। ईरान पुराने तेल टैंकरों के जरिए भी तेजी से आपूर्ति बढ़ा सकता है। यानी भारत को तेल प्राप्त करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के पूरी तरह खुलने का इंतजार जरूरी नहीं होगा। हालांकि, यह सब अंतत: डील के क्रियान्वयन और उससे जुड़ी शर्तों पर निर्भर करेगा।

सप्लाई में कब तक आएगी तेजी, 3 रिपोर्ट

1. ब्लूमबर्ग के मुताबिक कतर ने रास लाफान से गैस निर्यात की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए फारस की खाड़ी से तेल टैंकरों को रास लाफान के पास बुलाया गया है। कतर की कोशिश 60 दिनों के भीतर गैस सप्लाई की प्रक्रिया को सामान्य करने की है। यानी 60 दिनों बाद कतर युद्ध पूर्व की स्थिति में गैस की आपूर्ति शुरू कर सकता है।
2. पेंटागन ने हाल ही में एक रिपोर्ट व्हाइट हाउस को दी थी। इसमें कहा गया था कि होर्मुज के नीचे हर एक मीटर पर एक किलो बारूद बिछी हैं। इसे साफ करने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। यानी पूरी तरह से होर्मुज के रास्ते को क्लीन होने में 180 दिन का वक्त चाहिए।
3. जानकारों का कहना है कि होर्मुज के रास्ते को साफ होने में कम से कम 30 दिन लगेंगे। यह सब कुछ ईरान पर निर्भर करेगा। छोटे-छोटे तेल टैंकर अभी भी निकल रहे हैं। भारत का एक दिशा टैंकर ओमान के पास है, जो होर्मुज से निकलने की तैयारी में है। यानी गैस और तेल सप्लाई की प्रक्रिया होर्मुज के रास्ते शुरू हो चुकी है।

बिजनेस वर्ल्ड

फोर्स मोटर्स ने भारत में पेश किया 200,000वां मर्सिडीज-बेंज इंजन

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

फोर्स मोटर्स लिमिटेड ने आज पुणे के चाकण स्थित अपने अत्याधुनिक इंजन निर्माण संयंत्र से मर्सिडीज-बेंज के 2,00,000वें (2 लाखवें) इंजन के रोल-आउट की घोषणा की है, जो मर्सिडीज-बेंज के साथ इसकी विनिर्माण साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंजन निर्माण में दोनों कंपनियों का साथ वर्ष 1997 से है, जो अब एक व्यापक साझेदारी में बदल चुका है; इसमें भारत में उत्पादित होने वाली मर्सिडीज-बेंज की सभी कारों और एसयूवी के लिए इंजनों और एक्सल का विनिर्माण शामिल है। यह 2 लाखवें इंजन का कीर्तिमान आपसी विश्वास, तकनीकी उत्कृष्टता, साझा मूल्यों और भारत में विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। फोर्स मोटर्स द्वारा निर्मित यह विशेष 6-सिलेंडर एम256 इंजन मर्सिडीज-बेंज की जीएलएस 450 एसयूवी में लगाया गया है। इस अवसर पर फोर्स मोटर्स के प्रबंध निदेशक श्री प्रसन फिरोदिया और मर्सिडीज-बेंज के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। समारोह में मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी के बोर्ड सदस्य डॉ. योर्ग बुर्जर (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट), श्री मैथियास गाइसेन (सेल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस) और श्री माइकल शीबे (प्रोडक्शन, क्वॉलिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट) सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इनके अलावा मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री संतोष अय्यर, मर्सिडीज-बेंज इंडिया के कार्यकारी निदेशक और संचालन प्रमुख श्री व्यंकटेश कुलकर्णी तथा फोर्स मोटर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक-संचालन श्री प्रशांत ईनामदार भी मौजूद थे। साथ ही दोनों कंपनियों के कई अन्य प्रतिष्ठित अधिकारी एवं अतिथि भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मर्सिडीज-बेंज के साथ फोर्स मोटर्स की दीर्घकालिक साझेदारी और इस उपलब्धि पर श्री प्रसन फिरोदिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, फोर्स मोटर्स लिमिटेड ने कहा, जैसे-जैसे मर्सिडीज-बेंज भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है, फोर्स मोटर्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण, परिचालन उत्कृष्टता और भारत में विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव घटकों के उत्पादन में योगदान देकर इसके विकास को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

75000 कर्मचारी, 900 कंपनियां, ब्रिटेन को ऐसे फायदा पहुंचाता है भारत

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा समझौते से ब्रिटेन में भारतीय कंपनियों में कार्यरत लगभग 9095 प्रतिशत भारतीय पेशेवरों को लाभ मिलेगा। यह कदम कंपनियों की लागत घटाएगा और ब्रिटेन के बाजार में भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दोनों देशों ने 17 जून को घोषणा की कि सामाजिक सुरक्षा समझौता और व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई से लागू होंगे। डीसीसी का सीधा लाभ आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इंफोसिस को मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि भारतीय मूल के पेशेवर हर साल ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में लगभग 50 करोड़ डॉलर का योगदान देते हैं। इस समझौते के तहत भारत या ब्रिटेन की कंपनियों द्वारा अस्थायी रूप से भेजे गए कर्मचारी मेजबान देश में अधिकतम पांच साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से मुक्त रहेंगे। यह भारत की एक प्रमुख मांग थी। ब्रिटेन में लगभग 75,000 भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं, जबकि 900 से अधिक भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हैं। वहां एक पेशेवर का औसत वार्षिक वेतन लगभग 40,00050,000 पाउंड है। अनुमान के अनुसार, आम तौर पर वेतन का लगभग 15 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा अंशदान में जाता है। ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है। अधिकारी ने कहा, यदि कोई नियोक्ता भारत में कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान कर रहा है, तो उसे ब्रिटेन में भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए कवरेज सर्टिफिकेट देना होगा। 15 जुलाई से भारतीय नियोक्ता इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। यह छूट हालांकि, ब्रिटेन में अन्य विदेशी कंपनियों में काम करने वाले भारतीयों पर लागू नहीं होगी। यह समझौता अस्थायी विदेश नियुक्तियों पर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाएगा और भारत-ब्रिटेन सेवा क्षेत्र साझेदारी को मजबूत करेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन, भारत के 283 अरब डॉलर के आईटी उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और कुल निर्यात में लगभग 17 प्रतिशत योगदान देता है। भारत का ब्रिटेन को सेवा निर्यात 2024 में 21.6 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 13.7 अरब डॉलर था।

यमुना एक्सप्रेसवे बनेगा बड़ा इकोनॉमिक हब, ऐसे मिलेगा फायदा

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून को पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग के साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों, निवेश और रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को अपनी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आरपीएस-10/2026 का ड्रॉ आयोजित किया। यह योजना इसलिए भी खास रही क्योंकि इसमें कुल 973 आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए गए थे, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या एक लाख से अधिक पहुंच गई थी। ऐसे में हर प्लॉट के लिए बड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिला। दरअसल जेवर एयरपोर्ट के बाद इस पूरे इलाके की डिमांड काफी बढ़ गई है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं आने वाले समय में यह एक बड़ा इकोनॉमिक हब बनकर उभरेगा। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह एयरपोर्ट अब केवल हवाई यात्रा का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, औद्योगिक क्लस्टर और बिजनेस हब के रूप में व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम विकसित करेगा। वैश्विक मॉडल्स की तर्ज पर यह क्षेत्र एयरोसिटी के रूप में विकसित हो रहा है, जहां एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लॉजिस्टिक्स पार्क, इंडस्ट्रियल जोन, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंशियल टाउनशिप का तेजी से विस्तार हो रहा है बेहतर कनेक्टिविटी, फ्रेट कॉरिडोर और मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के कारण निवेश आकर्षण और बढ़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में इसका असर साफ दिख रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार, 2020 से 2025 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में अपार्टमेंट की कीमतें लगभग तीन गुना तक बढ़ चुकी हैं, जबकि प्लॉट की कीमतों में औसतन 1.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। कुछ माइक्रो-मार्केट्स में कीमतों में 5 गुना तक उछाल देखने को मिला है। आने वाले समय में यह तेजी जारी रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि अगले दो वर्षों में प्लॉट की कीमतों में करीब 28% और अपार्टमेंट की कीमतों में 22% तक और वृद्धि हो सकती है। एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित सेक्टर, खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे का सेक्टर 22, हाउसिंग डिमांड का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां कई बड़े डेवलपर्स ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में 3बीएचके अपार्टमेंट की कीमत करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच है, जबकि करीब 600 वर्गफुट के स्टूडियो अपार्टमेंट लगभग 85 लाख रुपए में उपलब्ध हैं।

हैदराबाद में खुला देश का सबसे बड़ा पोर्श सेंटर, लग्जरी कार ब्रांड ने बढ़ाई मौजूदगी

हिंदमाता नेटवर्क @ हैदराबाद

लग्जरी कार निर्माता पोर्श ने हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डीलरशिप सेंटर खोलकर भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। करीब अट्ठाईस सौ वर्ग मीटर में फैली इस सुविधा में बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। यह देश का तीसरा संयुक्त केंद्र है, जो बेंगलुरु और चेन्नई की श्रृंखला में जुड़ गया है। इसके साथ ही पोर्श के देश भर में बिक्री केंद्रों की संख्या चौदह और सर्विस केंद्रों की संख्या दस हो गई है। राजधानी के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों के निकट स्थित इस नए सेंटर को डेस्टिनेशन पोर्श कॉन्सेप्ट के तहत डिजाइन किया गया है, जहां ग्राहक पारंपरिक खरीदारी के अनुभव से हटकर एक जीवनशैली-आधारित माहौल में ब्रांड से जुड़ सकते हैं। पोर्श इंडिया के प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने कहा कि हैदराबाद महत्वाकांक्षा और उद्यमशीलता का शहर है, और यह केंद्र प्रदर्शन, इंजीनियरिंग सिद्धांतों और दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सेंटर का संचालन ईवीएम प्रीमियम कार्स के साथ साझेदारी में किया जा रहा है, जो सन दो हजार तेरह से पोर्श से जुड़ा हुआ है। डीलर प्रिंसिपल साबू जॉनी ने कहा कि यह केंद्र विश्वस्तरीय शोरूम अनुभव और उच्च प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञता के साथ क्षेत्र के ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए तैयार किया गया है। पोर्श इंडिया ने यह स्पष्ट किया है कि वह देश के प्रमुख महानगरीय बाजारों में अपने नेटवर्क का विस्तार जारी रखेगा।

अफगानिस्तान में स्मार्टफोन पर लगा बैन

तालिबान का आदेश न मानने पर होगी जेल, छिन जाएगी सरकारी नौकरी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और बहुत ही कड़ा फैसला लागू कर दिया है। देश के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने सभी विभागों को स्पष्ट आदेश जारी किया है। इस नए फरमान के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। इसका असर शिक्षकों और सभी बड़े-छोटे अधिकारियों के दैनिक काम पर बुरी तरह पड़ रहा है। देश के सैन्य और नागरिक दोनों विभागों के कर्मचारियों पर यह कड़ा नियम बुधवार से पूरी तरह लागू हो गया है। अगर कोई भी कर्मचारी इस नए नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा नियम तोड़ने वालों को छह महीने तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। व्हाट्सऐप और एआई टूल्स के बिना सरकारी काम करना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के चिन्ह वाला आदेश

स्मार्टफोन पर बैन लगाने वाला यह आदेश पिछले सप्ताह ही सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा था। इस आदेश पत्र पर अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह भी प्रमुखता से लगा हुआ था। सभी प्रांतों के विभाग प्रमुखों को 17 जून से इस प्रतिबंध को पूरी तरह लागू करने की सलाह दी गई थी। सिर्फ सुप्रीम लीडर की खास अनुमति मिलने पर ही किसी कर्मचारी को स्मार्टफोन उपयोग की विशेष छूट मिल सकती है। सूचना विभाग के कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि नियम का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। पकड़े जाने पर न केवल नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।

नेपाल में बिहार के 5 लड़के गिरफ्तार

15 वर्षीय नेपाली लड़के के अपहरण का आरोप

हिंदमाता नेटवर्क @ काठमांडू

नेपाल की राजधानी काठमांडू से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने एक किडनैपिंग केस में भारत के पांच टीनेजर्स को गिरफ्तार किया है। काठमांडू के एक होटल में चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, पुलिस ने बंधक बनाए गए 15 वर्षीय एक नेपाली लड़के को सुरक्षित छुड़ा लिया और अपहरण के आरोप में 5 भारतीय टीनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक, इस पूरी साजिश की शुरुआत सोमवार को हुई थी। बताया जा रहा है कि भारतीय टीनेजर्स ने काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित चितवन जिले से 15 साल के एक नेपाली लड़के का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद आरोपी लड़के को लेकर काठमांडू आ गए और यहां के एक होटल को अपना ठिकाना बनाया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 15 साल के लड़के को बंधक बनाकर रखने के बाद किडनैपर्स ने उसके परिवार से फिरौती की मांग की थी। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मंगलवार को होटल में छापा मारकर अपहरण में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग बिहार के बेतिया के रहने वाले 18 साल के लड़के हैं। पुलिस ने आगे जानकारी दी कि बचाव अभियान के दौरान अगवा किए गए लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं, गिरफ्तार टीनेजर्स को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए चितवन जिला पुलिस के पास भेज दिया गया है।

अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते पर लगी मुहर

ट्रंप और पेजेशकियान ने खत्म की महीनों पुरानी जंग

हिंदमाता नेटवर्क @ वॉशिंगटन

वैश्विक राजनीति के मंच से एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चला आ रहा खतरनाक सैन्य और कूटनीतिक संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बुधवार को एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसे विश्व शांति की दिशा में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

वर्साय के ऐतिहासिक महल में लगी मुहर

इस समझौते का महत्वपूर्ण पल फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में देखने को मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ डिनर पर मौजूद थे। इसी दौरान ट्रंप ने समझौते की हार्ड कॉपी पर अपने हस्ताक्षर किए और पत्रकारों के सामने गर्व से चिल्लाते हुए कहा इट्स साइन्ड।

60 दिनों का रेस्टोरेंट पीरियड

इस समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि अगले 60 दिनों तक दोनों देशों को पूर्ण संयम बरतना होगा। इस अवधि के दौरान अमेरिका और ईरान दोनों ही किसी भी ऐसे सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक कदम से बचेंगे, जिससे आपसी विश्वास को ठेस पहुंचे या समझौते के क्रियान्वयन में बाधा आए। हालांकि, इस समझौते की नींव रविवार को ही रख दी गई थी, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वातार्कार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देशों के वार्ता दलों की एक और महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जहां इस ढांचे को एक स्थायी और पूर्ण समझौते में बदलने पर चर्चा होगी।

यह हमला जायज है, मॉस्को की रिफाइनरी फूंकने के बाद जेलेंस्की की रूस को खुली चुनौती, दहला पुतिन का गढ़

हिंदमाता नेटवर्क @ मॉस्को

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार वर्षों से अधिक समय से जारी भीषण सैन्य संघर्ष ने गुरुवार को एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी शहर मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले के प्रभाव को देखते हुए रूस ने मॉस्को के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों के संचालन को पूरी तरह से निलंबित कर दिया है।

रिफाइनरी पर हमला जायज

इस महाहमले के तुरंत बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली है। जेलेंस्की ने बताया कि यह हमला कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसी सप्ताह में दूसरी बार मॉस्को की एक बड़ी तेल रिफाइनरी को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और तस्वीरों में रिफाइनरी से उठते काले धुएं के गुबार ने हमले की भयावहता को स्पष्ट कर दिया है।

मॉस्को के आसमान में ड्रोन

रूस की नागरिक उड्डयन संस्था रोसावियात्स्य ने इस आपातकालीन स्थिति की पुष्टि की है। संस्था के अनुसार, हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। रूसी रक्षा अधिकारियों का दावा है कि उनके वायु रक्षा तंत्र ने मॉस्को की सीमा के भीतर लगभग 180 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में ड्रोनों का राजधानी तक पहुंच जाना रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

रूस के अन्य क्षेत्रों में भी तबाही

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी खुलासा किया कि उनके सैनिक केवल मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने रूस के रोस्तोव प्रांत और यूक्रेन के उन हिस्सों में भी कई रूसी सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है, जिन पर रूस का अवैध कब्जा है। इन चौतरफा हमलों के बाद अब पूरे रूस में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

'अपनी सुरक्षा खुद करो', अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ ने यूरोपीय देशों को लताड़ा

हिंदमाता नेटवर्क @ वॉशिंगटन

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को नाटो देशों की बैठक में यूरोपीय सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घोषणा की कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैन्य बलों की अगले छह महीनों में व्यापक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी इस बात पर निर्भर करेगी कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी तेजी और गंभीरता से अपने हाथ में लेते हैं। ब्रुसेल्स में नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने कहा कि यह केवल औपचारिक समीक्षा नहीं होगी, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूरोप अपनी रक्षा का नेतृत्व स्वयं करे और अमेरिका पर निर्भरता कम करे। हेगसेथ ने आरोप लगाया कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के दौरान कुछ यूरोपीय सहयोगियों ने अमेरिकी सेना को अपने सैन्य अड्डों, हवाई मार्गों और आवश्यक सुविधाओं के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि सहयोगी देशों के इस रवैए ने अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला।

यूरोप की नीतियों पर भी साधा निशाना

अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यूरोपीय देशों की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूरोप ने टैंक, लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रक्षा संसाधनों की बजाय जेंडर इक्विटी, जलवायु परिवर्तन और कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया, जिससे रक्षा बजट प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूरोप ने अपनी सीमाएं लंबे समय तक खुली रखीं और रक्षा तैयारियों की अनदेखी की।

'नाटो 3.0' बनाना चाहता है ट्रंप प्रशासन

हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन नाटो को एक नए स्वरूप 'नाटो 3.0' में बदलना चाहता है, ताकि संगठन भविष्य के किसी भी खतरे का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका अब अपनी सैन्य प्राथमिकताओं का पुनर्गठन कर रहा है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन से संभावित टकराव को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को पुनर्संतुलित करना चाहता है।

हिंदमाता एंकर भारत ने ऐसे ही एक सैन्य समझौते का बेहतरीन इस्तेमाल साल 2020 में चीन के साथ हुए तनाव के दौरान बड़ी ही समझदारी से किया था

भारत में 3000 रूसी सैनिकों की तैनाती और सैन्य लॉजिस्टिक समझौते का क्या है असली सच?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक अहम सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता यानी कि रीलोस इसी साल जनवरी महीने से पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इस शानदार समझौते पर पिछले कई सालों से लगातार बहुत ही गहन विचार-विमर्श किया जा रहा था। जब से यह खास समझौता हुआ है तब से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद रूसी पक्ष ने यह बड़ा दावा किया था कि भारत की जमीन पर 3000 रूसी सैनिक तैनात हो सकेंगे। इसके साथ ही भारत के भी 3000 सैनिक रूस में तैनात होने की बात कही गई थी। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे एक बहुत ही बड़े और स्थायी सैन्य समझौते के रूप में जोर-शोर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों ने अब इस पूरे समझौते की वास्तविकता और इसकी अहम शर्तों को देश के सामने स्पष्ट कर दिया है।

समझौते की अहम शर्तें और नियम

विशेषज्ञों के अनुसार भारत और रूस के बीच हुआ यह लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता ठीक वैसा ही है जैसा अन्य देशों के साथ है। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि यह मूलभूत सैन्य सहयोग समझौता है जिसमें ठिकाने और बंदरगाह इस्तेमाल होते हैं। दोनों देश एक-दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल सप्लाई, ईंधन और जरूरी रिपेयरिंग कार्यों के लिए बहुत ही आसानी से कर सकेंगे।

सैनिकों की स्थायी तैनाती का सच

साल 2017 में तत्कालीन भारतीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि ऐसे समझौते सैन्य अड्डे बनाने के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं। इसके तहत खाना, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सेवाएं, पेट्रोल और कपड़ों जैसी कई मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। 3000 सैनिकों की जो संख्या बताई गई है वह केवल एक ऊपरी सीमा है जो विमानों और युद्धपोतों के साइज पर निर्भर करती है।

50 हजार सैनिकों की मदद का उदाहरण

भारत ने ऐसे ही एक सैन्य समझौते का बेहतरीन इस्तेमाल साल 2020 में चीन के साथ हुए तनाव के दौरान बड़ी ही समझदारी से किया था। उस समय भारत ने लद्दाख में तैनात अपने 50 हजार सैनिकों के लिए जाड़े के कपड़े बहुत ही कम समय में मंगाए थे। रूस के साथ हुए इस नए और अहम रीलोस समझौते की वैधता फिलहाल 5 साल के लिए ही तय की गई है।

भारतीय सैनिक जाएंगे आर्कटिक

रूस के साथ हुए इस शानदार समझौते में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि दोनों देश एक-दूसरे के यहां स्थायी सैनिक तैनात करेंगे। हालांकि इस डील का सबसे अहम फायदा यह है कि भारतीय सैनिक आर्कटिक में रूसी सैन्य ठिकाने तक आसानी से जा सकेंगे। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ भी इसी तरह के समझौते पहले ही किए हुए हैं।

दैनिक ठाणे, शुक्रवार 19 जून, 2026
हिंदमाता मिरर
पैनी नजर, पुख्ता खबर
GAME & GLAMOUR

'बंटवारा 1947' का टीजर रिलीज

'बंटवारा 1947' इस साल की सबसे बेसब्री से इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। अपने शानदार मोशन पोस्टर और किरदारों के दमदार पोस्टर्स के रिलीज होने के बाद से ही, इस फिल्म ने हर तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। यह एक ऐसी कहानी के लिए उत्सुकता बढ़ा रही है जो हिम्मत, बलिदान और कभी न टूटने वाले इंसानी जज्बे से जुड़ी है।

■ अब, इसके दमदार टीजर के रिलीज होने के साथ ही, फिल्म को लेकर बना हुआ एक्साइटमेंट एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। 'बंटवारा 1947' का यह दिलचस्प और इंटेंस टीजर दर्शकों को इतिहास के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक में ले जाता है, भारत की आजादी और वो दर्दनाक बंटवारा जिसने एक देश को बांट दिया और हमेशा के लिए करोड़ों जिंदगियों को बदल कर रख दिया। दमदार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर से भरा यह टीजर इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे चैप्टर के दौरान उम्मीद और लचीलेपन के जज्बे को दिखाता है। हमारी इस कहानी के केंद्र में एक ऐसा हीरो है जो डर और नफरत से ऊपर उठकर असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है।

■ 'बंटवारा 1947' में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे शानदार कलाकारों की फौज है। यह फिल्म करीब तीन दशकों के बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की बहुप्रतीक्षित (मोस्ट-अवेडेड) वापसी को भी दिखाती है। 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' को नेशनल अवार्ड विनर फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। इसका म्यूजिक ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 'पार्टीशन डे' के मौके पर 14 अगस्त 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

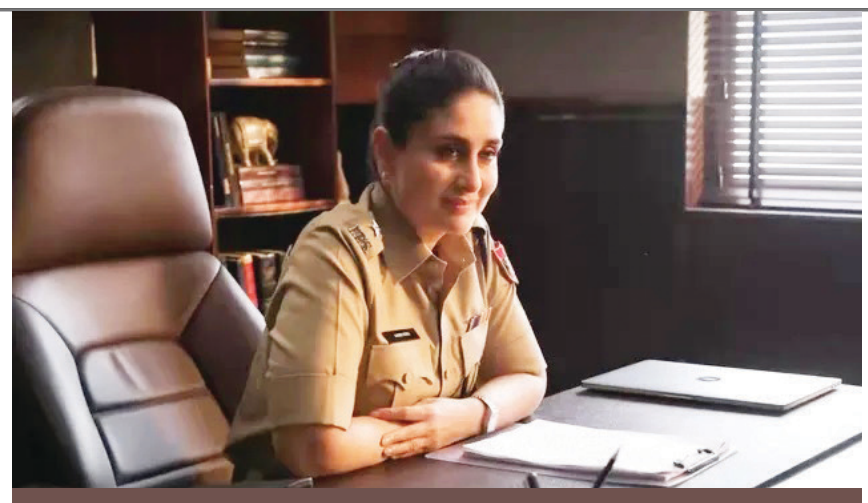

'लेडी सिंघम' बनीं करीना कपूर

सैम बहादुर और राजी जैसी शानदार फिल्में बनाने वालीं निर्देशक मेघना गुलजार आने वाले समय में फिल्म दायरा से दर्शकों का मनोरंजन करती हुई नजर आएंगी। लंबे समय से दायरा की चर्चा चल रही है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और साउथ अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कलाकार अहम किरदार में मौजूद हैं। गुरुवार को दायरा फिल्म की पहली झलक बीटीएस (BTS) वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर सामने आई है। साथ ही मेकर्स की तरफ से इसकी रिलीज डेट का खुलासा भी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि दायरा सिनेमाघरों में कब आएगी।

दायरा की पहली झलक

अभिनेता पृथ्वीराज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दायरा का एक लेटेस्ट बीटीएस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनके साथ करीना कपूर भी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में मौजूद हैं। दायरा के इस बीटीएस वीडियो से कन्फर्म होता हो कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसको मेघना गुलजार ने अपना डायरेक्शन के दम पर सिनेमाई नजरिए से पेश किया है। वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दायरा एक सस्पेंस से भरपूर थ्रिलर होगी, जोकि मर्डर मिस्ट्री या किसी बड़ी घटना के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दायरा के बीटीएस वीडियो ने फैंस की एक्साइटमेंट को हाई कर दिया है। ऐसे में अब प्रशंसक इसकी रिलीज के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। गौर करें दायरा की रिलीज डेट की तरफ तो ये फिल्म 18 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

करीना कपूर की वापसी

करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद करीना कपूर खान बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। आखिरी बार वह बॉलीवुड फिल्म सिंघम अगेन में नजर आई थीं, जिसको बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक प्रदर्शन करने में ही सफल हो सकी थी। उम्मीद है कि दायरा के जरिए करीना एक ग्रैंड कमबैक करती हुई दिखाई दे सकती हैं।

यामी गौतम ने किए महाकालेश्वर के दर्शन

अभिनेत्री यामी गौतम ने अपने परिवार के साथ उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। जानिए पहली बार महाकाल के दर्शन करने पर यामी को कैसा लगा?

पहली बार मिले दर्शन

बातचीत के दौरान यामी ने बताया कि उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन पहली बार उन्हें यहां आने का सौभाग्य मिला। इससे पहले वे फिल्म 'ओह माय गॉड 2' की शूटिंग के लिए उज्जैन आई थीं, पर तब मंदिर नहीं जा पाई थीं। इसके साथ ही यामी ने मंदिर की अच्छी व्यवस्था और सफाई के लिए वहां के अधिकारियों की तारीफ भी की। मंदिर के दर्शन के लिए यामी ने एक बेहद साधारण और सुंदर गुलाबी रंग का सलवार-सूट पहना हुआ है।

यामी और आदित्य की मुलाकात

यामी और आदित्य की मुलाकात फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के सेट पर हुई थी। दोनों को एक-दूसरे से प्यार हुआ और जून 2021 में उन्होंने शादी कर ली थी। मई 2024 में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने वेदाविद रखा है।

यामी का वर्कफ्रंट

यामी को आखिरी बार मुख्य भूमिका में साल 2025 में आई फिल्म 'हक' में देखा गया था, जिसमें 'शाह बानो' के रूप में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म 'धुरंधर 2' में एक कैमियो रोल किया था, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यामी गौतम अपनी आगामी फिल्मों में 'नई नवेली', 'चोर निकल के भागा 2', और 'तामसुर' में मुख्य भूमिका निभाती नजर आ सकती हैं।

जैकलीन करेंगी हॉरर जॉनर में डेब्यू

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस जल्द ही अपनी पहली पूर्ण हॉरर फिल्म के साथ इस शैली में कदम रखने जा रही हैं। अभिनेत्री काफी समय से इस जॉनर में एक मजबूत और अलग कहानी की तलाश में थीं और अब उन्हें ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया है जिसने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया है।

■ सूत्रों के अनुसार, यह फिल्म हॉरर, इमोशन और म्यूजिक का बेहतरीन मिश्रण होगी, जो दर्शकों को एक संपूर्ण सिनेमाई अनुभव देगी। फिल्म में जैकलीन मुख्य भूमिका निभाएंगी, जबकि दो मेल एक्टर्स को पहले ही फाइनल किया जा चुका है। फिलहाल फिल्म का टाइटल, अन्य कलाकारों के नाम और निर्देशक की जानकारी गुप्त रखी गई है। इस फिल्म का निर्माण ख्याति मदान के बैनर नॉट आउट एंटरटेनमेंट के तहत बड़े स्तर पर किया जाएगा। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।

■ सूत्रों का यह भी कहना है कि फिल्म का एक टीजर और एक गाना पहले ही शूट किया जा चुका है, जबकि कलाकार इन दिनों वर्कशॉप्स में हिस्सा ले रहे हैं। फिल्म की शूटिंग इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि जैकलीन इससे पहले भूत पुलिस में नजर आ चुकी हैं, लेकिन वह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म थी। यह नई फिल्म उनके करियर की पहली पूरी तरह हॉरर फिल्म होगी। वर्कफ्रंट की बात करें तो जैकलीन हाल ही में हाउसफुल 5 में नजर आई थीं और अब वह वेलकम टू द जंगल में दिखाई देंगी, जो 26 जून 2026 को रिलीज होने वाली है।

'द इंडिया स्टोरी' का पोस्टर रिलीज

एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े अगली फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की पहली झलक सामने आ गई है, जिसके बाद से ही फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

इस मुद्दे पर है फिल्म

'द इंडिया स्टोरी' फिल्म खाने में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है और एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा पेश करने वाली है। पोस्टर में श्रेयस तलपड़े एक बीमार छोटी बच्ची को गोद में उठाए नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में बॉम्बे हाई कोर्ट दिखाया गया है। साथ ही एक कीटनाशक (पेस्टिसाइड) का सिलेंडर गवाह के बॉक्स में रखा हुआ नजर आता है, जो इस बात का इशारा करता है कि फिल्म में कानूनी लड़ाई अहम भूमिका निभाएगी।

चेतन डीके ने किया है निर्देशन

यह पोस्टर साफ दिखाता है कि फिल्म खाने में मिलावट के खतरनाक असर को दिखाएगी और बताएगी कि यह समस्या देश के लाखों परिवारों को कैसे प्रभावित करती है। फिल्म का मकसद लोगों को इस गंभीर मुद्दे के प्रति जागरूक करना है, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है और इसे सागर बी शिंदे ने लिखा और प्रोड्यूस किया है। फिल्म में भारत के एक बड़े लेकिन कम चर्चा में रहने वाले पब्लिक हेल्थ इश्यू को दिखाया जाएगा।

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म के को-प्रोड्यूसर्स में स्वाति विनायक सैंदाने, अनीता जाधव, विनायक सैदानी, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी शामिल हैं। वहीं फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमैटोग्राफर निशांत भगवत, म्यूजिक कंपोजर मंगेश धाकड़े, एडिटर आशीष म्हात्रे, गीतकार शकील आजमी और साउंड डिजाइनर अनमोल भावे हैं। 'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दुनियाभर में रिलीज की जाएगी।

राधा-कृष्ण की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं इम्तियाज अली

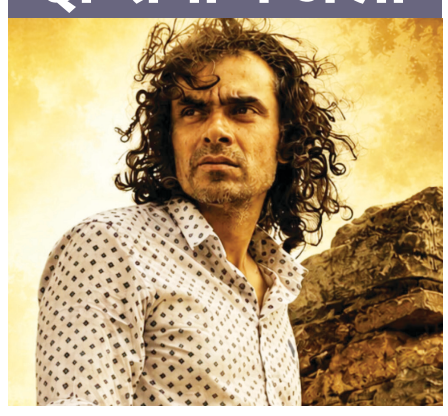

इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा की हर जगह तारीफ हो रही है। मैं वापस आऊंगा की तारीफों के बीच इम्तियाज अली ने कहा कि वो राधा-कृष्ण की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राधा-कृष्ण की कहानी केवल एक लव स्टोरी नहीं है। इसी बातचीत के दौरान इम्तियाज अली ने कहा कि वो हर चीज में रोमांस डालना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप हो जाता है।

लव स्टोरी बनाने को लेकर क्या बोले इम्तियाज अली?

एबीपी लाइव के साथ खास बातचीत में इम्तियाज अली ने कहा कि मैं हर चीज में रोमांस नहीं डालना चाहता, लेकिन वो अपने आप हो जाता है, तो मैं बस उसे रोकता नहीं हूं। मैं वापस आऊंगा डायरेक्टर ने कहा कि वो लव आजकल को लव स्टोरी की तरह नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कोई भी फिल्म लव स्टोरी की तरह नहीं बनाई है। जब लव आजकल का नाम तय हो रहा था, उन्हें लगा था कि आज कल एक बेहतर नाम होगा। उन्होंने कहा कि वो सोचते थे कि क्या ये लव स्टोरी है भी या नहीं।

लव आजकल को लेकर इम्तियाज अली ने कही ये बात

इम्तियाज ने आगे कहा कि उनकी टीम ने उन्हें बताया कि कैसे वो उस फिल्म को लव स्टोरी की तरह देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस फिल्म को अलग-अलग दौर में प्यार की एक व्याख्या के तौर पर देखा। इम्तियाज ने कहा कि उन्होंने जब वी मेट को बिल्कुल भी लव स्टोरी की तरह नहीं बनाया था, लेकिन ये उनकी फिल्म में बार-बार आ जाता है।

राधा-कृष्ण पर कहानी बनाना चाहते हैं इम्तियाज अली

इम्तियाज से जब पूछा गया कि वो फ्यूचर में कैसी कहानियां बनाना चाहते हैं, तब उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि हिंदी पौराणिक कथाओं में बहुत सी कहानियां हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं। मैंने पहले भी ये कहा है। मैं राधा-कृष्ण की कहानी बनाना चाहता हूं। जब इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने कहा कि ये भी एक लव स्टोरी है, तो उन्होंने कहा कि राधा-कृष्ण की कहानी केवल एक लव स्टोरी नहीं है। उस कहानी में बहुत सी परते हैं। इसके पीछे एक गहरा दर्शनशास्त्र है। जब वी मेट डायरेक्टर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप प्यार के बिना कोई कहानी बना सकते हैं। वो प्यार आपके देश के प्रति हो सकता है, या फिर किसी ऐसे के लिए जो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, और कोई इसका बदला ले रहा है, लेकिन वो कहानी हमेशा प्यार के बारे में होगी। आप उसे अलग तरीके से दिखा सकते हैं।

आलिया भट्ट ने बताया संगीत और डांस की शौकीन है राहा

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आगामी फिल्म अल्फा को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका फैंस को लम्बे समय से इन्तजार है। फिल्म के प्रमोशन में जुटी आलिया हाल ही में एक कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात की बल्कि अपनी बेटी राहा कपूर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा की।

फंको बहुत पसंद है स्पोर्ट्स

इंटरव्यू के दौरान आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा कपूर के बारे में दिलचस्प बातें साझा की। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें अभिनय का शोक था और वह अक्सर आईने के सामने खड़े होकर परफॉर्म किया करती थीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहा भी आगे चलकर फिल्मों में आ सकती है तो आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि राहा में भी मंच पर छा जाने वाली खूबियां नजर आती हैं। आलिया के मुताबिक, राहा की रुचियां काफी विविध हैं। उसे खेल-कूद और अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लेना पसंद है। इसके अलावा वह संगीत और डांस की भी शौकीन है। आलिया ने बताया कि राहा गानों को बड़े ध्यान से सुनती है और नृत्य करना उसे बेहद पसंद है। खास बात यह है कि वह डांस के स्टेप्स बहुत तेजी से सीख लेती है, जिससे उसकी प्रतिभा साफ झलकती है।

बहुत जल्दी चीजें समझती है राहा कपूर

इसके बाद आलिया ने बताया कि राहा अभी छोटी है लेकिन बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। वो किसी भी चीज को देखते ही उसे अडॉप्ट कर लेती है। इसी के साथ एक बार आलिया भट्ट की बड़ी बहन पूजा भट्ट ने भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि राहा का जन्म ही एक्ट्रेस बनने के लिए हुआ है। उसके अंदर एक अलग ही जुनून और चमक है, चाहे वो छोटी है लेकिन जिस भी महफिल में जाती है, उसमें रौनक और भी बढ़ जाती है।

अदा शर्मा ने किया फिल्म 'गजरा' का एलान

'द केरल स्टोरी' और '1920' जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाली अदा शर्मा अब मराठी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं। उनकी पहली फिल्म होगी 'गजरा'। इसका ऐलान हो गया है। साथ ही पहली झलक भी सामने आई है।

आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत

अदा शर्मा की डेब्यू मराठी फिल्म 'गजरा' का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी। अदा इसमें लीड रोल निभाती नजर आएंगी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर कर यह जानकारी साझा की है। साथ ही लिखा है कि मराठी में मेरी पहली फिल्म 'गजरा'। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। अदा शर्मा ने आगे लिखा है कि मेरी पहली फिल्म '1920' से 'केरल स्टोरी', 'सनफ्लावर', 'कमांडो', 'बस्तर', 'रीता सान्याल' तक, आपने मुझे बहुत प्यार दिया।

मोनालिसा का अप्सरा लुक

मोनालिसा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। एक बार फिर वे अपने लुक को लेकर छा गई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिनमें वे किसी अप्सरा सी खूबसूरत लग रही हैं। मोनालिसा की ये फोटोज उनके नए किरदार की हैं, जिसे वे एक शो में निभाती दिखेंगी। फिलहाल, वे शो की शूटिंग कर रही हैं।

■ मोनालिसा इस शो में वसंतसेना का किरदार निभाती नजर आएंगी। साझा की गई तस्वीरों में वे बला की खूबसूरत लग रही हैं, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। मोनालिसा ने तस्वीरों के साथ लिखा है कि सुंदर सुंदर। वसंतसेना। अभिनेत्री गुजरात के उमरगाम में फिलहाल इस शो की शूटिंग कर रही हैं। वसंतसेना प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य के नाटक 'मृच्छकटिकम्' की मुख्य नायिका है, वह उज्जयिनी की एक बेहद धनी, खूबसूरत और कला प्रेमी नगरवधू थीं। मोनालिसा का यह अंदाज देख फैंस क्रेजी हो रहे हैं और तारीफों की झड़ी लगा दी है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक नरेश पी. बजाज द्वारा बैरक नंबर 887/27 सेक्शन 18, उल्हासनगर -421 003, जिला ठाणे से प्रकाशित व सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, आमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनवाला क्रॉस रोड -2, जवाहरनगर के पास, फाटक पुल, गोरेगांव, मुंबई -63, (महाराष्ट्र) से मुद्रित।
दूरध्वनि: 0251- 3238100, **कार्यकारी संपादक:** पंजू बजाज (पी. आर. बी. एक्ट के तहत कंटेट चयन के लिए जिम्मेदार) न्याय क्षेत्र ठाणे जिला। **hindmatamirror1@gmail.com** RNI. NO. MAHHIN/2011/43060 **स्थानीय संपादक:** शिवप्रताप